वर्ष-10, अंक-5, फरवरी-2025

मूल्यः ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

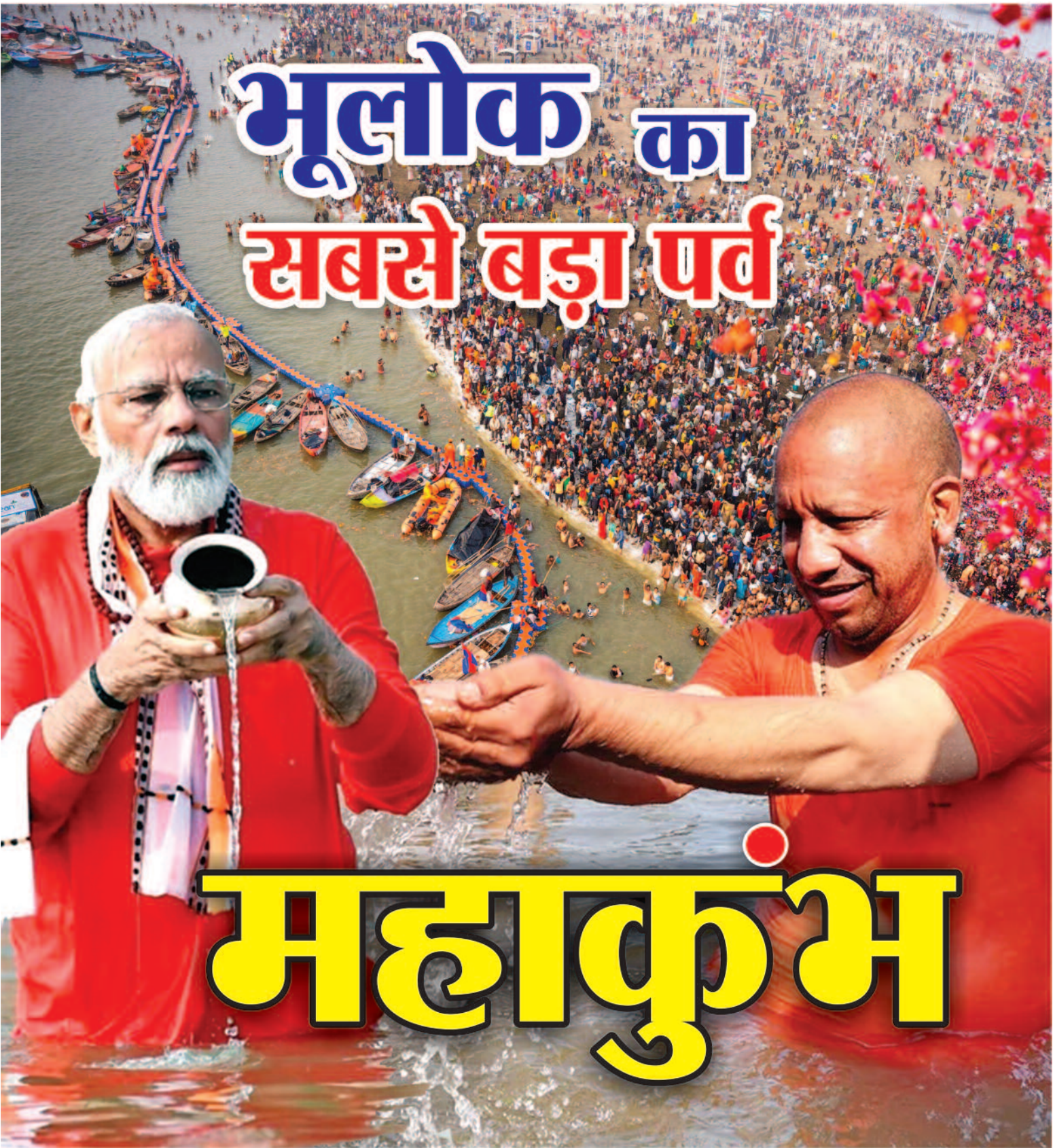

भूलोक का सबसे बड़ा पर्व

महाकुंभ

संगम में पुण्य
सुविधाओं का महाकुम्भ

दिव्य-भव्य-डिजिटल
एकता का महाकुम्भ

स्वस्थ महाकुम्भ

• सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में 6,000 बेड तैयार • मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल, 381 चिकित्सक तैनात • 125 रोड, 7 रिवर एवं एक एयर एम्बुलेंस तैनात • प्रमुख मार्गों पर स्थित सीएचसी/पीएचसी का अपग्रेडेशन

स्वच्छ महाकुम्भ

• 850 समूहों में 10,200 स्वच्छताकर्मियों की तैनाती • स्वच्छता निगरानी के लिए 1,800 गंगादूतों की तैनाती • 25,000 लाइनर बैगयुक्त डस्टबिन, 300 सक्शन गाड़ियां • जीपीएस से लैस 120 टिपर-हापर और 40 कॉम्पेक्टर ट्रक

सुरक्षित महाकुम्भ

• 37,000 पुलिसकर्मी एवं 14,000 होमगार्ड की तैनाती • 2,750 एआई बेस्ड सीसीटीवी एवं 80 वीएमडी टीवी स्क्रीन • 3 जल पुलिस स्टेशन, 18 जल पुलिस कंट्रोल रूम • 50 फायर स्टेशन, 20 फायर पोस्ट, 50 वॉच टावर, 4,300 फायर हाइड्रेंट

• 4,000 हेक्टेयर में विस्तृत • 25 सेक्टर में सुव्यवस्थित • 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग • 1,50,000 शौचालय • 1,60,000 सुसज्जित टेंट • 67,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट • 2 नए विद्युत सब स्टेशन • 66 नए विद्युत ट्रांसफॉर्मर • 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट • 1,249 किमी पेयजल पाइपलाइन • 200 वाटर एटीएम • 85 नलकूपों की स्थापना • 7,000 बस का बेड़ा • 550 शटल बस का बेड़ा • 7 नए बस स्टॉप • 30 पाण्टून ब्रिज (400 किमी में) • 9 पक्के घाटों की स्थापना • 7 रिवर फ्रंट रोड • 12 किमी में अस्थायी घाट • 14 नए फ्लाईओवर एवं अंडरपास • 11 नए कॉरिडोर का विकास • 3,000 स्पेशल सहित 13,000 रेल गाड़ियां • प्रयागराज एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल

सनातन गर्व, महाकुम्भ पर्व

• श्रद्धालुओं-पर्यटकों की मदद के लिए ट्रैवल गाइड • मार्गदर्शन के लिए कुम्भ सहायक AI चैटबॉट • मानसिक शांति के लिए बर्ड साउंड थेरेपी • देशभर के हस्तशिल्पियों/कारीगरों का संगम • संगम में श्रद्धालुओं को बोट राइड की सुविधा • वेदों-पुराणों की कथा का बखान करते चौराहे • सांस्कृतिक मंचों पर गायन/वादन/नृत्य प्रस्तुतियां • प्रत्येक दिशा में वाहन पार्किंग की उत्तम व्यवस्था • प्रत्येक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती • हाईवे के थानों पर भी चिकित्सा सुविधा

मेला प्रशासन | आवास एवं आहार

कुम्भ सहायक
पर 'नमस्ते' भेजें

महाकुम्भ हेल्पलाइन	1920	112	1010	102, 108	18004199139
	महाकुम्भ मेला हेल्पलाइन	इमरजेंसी सर्विस	खाद्य एवं रसद हेल्पलाइन	एम्बुलेंस सेवा	रेलवे हेल्पलाइन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP mahakumbh_25/ upmahakumbh MahaKumbh_2025 https://kumbh.gov.in/

वर्ष- 10 अंक- 5

फरवरी - 2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेलः winews.in@gmail.com
वेबसाइटः www.winews.in
सम्पर्क सूत्रः 9891116568

नोटः पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

अन्दर के पेजों में...

सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट से भारत निर्माण को मिलेगी गति — पेज 03

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 8.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक बजट — पेज 08

नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम के मिलने लगे हैं बेहतर नतीजे — पेज 16

दिल्ली की किस्मत 'रेखा गुप्ता' से एनसीआर की अपेक्षाएं — पेज 22

आखिर कौन, कैसे और कब तक पाएगा भीड़ से उत्पन्न भगदड़ पर काबू? — पेज 42

मोदी का मोटापामुक्त भारत स्वास्थ्य-क्रांति का आधार — पेज 48

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

'फ्री की राजनीति' पर जनता का फैसला, दिल्ली का रुख बदला

ललित कुमार
सम्पादक

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित नहीं कहे जा सकते। यह चुनाव शुरू से दो-ध्रुवीय था। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी। कांग्रेस ने जरूर दावेदारी की थी, मगर जैसे-जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती गई, उसे अहसास होने लगा था कि वह मुकाबले में नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे शिथिलता ने घेर लिया। भाजपा लंबे समय से आम आदमी पार्टी की कमजोरियों और अनियमितताओं को उजागर करती आ रही थी। इस तरह वह लोगों के मन में सत्ताविरोधी लहर पैदा करने में कामयाब भी हुई। हालांकि तमाम सर्वेक्षणों से यही पता चल रहा था कि दिल्ली की बड़ी आबादी आम आदमी पार्टी सरकार से बहुत नाखुश नहीं थी, मगर उनमें से काफी लोग इस बार बदलाव चाहते थे। आम आदमी पार्टी की साख को सबसे अधिक नुकसान कथित शराब घोटाले की वजह से हुआ। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। पार्टी लगातार दलील देती रही कि उसके नेताओं को झूठे आरोप में फंसाया गया है, मगर वह लोगों के गले नहीं उतरी। उन्होंने दागी नेताओं को शिकस्त दी। इन नतीजों से यह भी जाहिर हुआ है कि भाजपा के काम पर लोगों का भरोसा कमजोर नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों से अधिक मुफ्त की योजनाओं का शोर सुनाई दिया। आम आदमी पार्टी सरकार पहले से मुफ्त बिजली-पानी और शिक्षा-स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचा रही थी। इसे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक आकर्षण बना हुआ था। फिर सरकार ने चुनाव से ऐन पहले घोषणा कर दी कि वह हर महिला को इक्कीस सौ रुपए हर महीने देगी। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया। इसके जवाब में भाजपा ने ढाई हजार रुपए हर महीने देने की घोषणा कर दी। फिर यह भी भरोसा दिलाया कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, अगर उसकी सरकार बनी तो, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इस वादे पर लोगों ने भरोसा किया। दूसरे कुछ राज्यों में भी भाजपा महिलाओं के लिए नगद राशि देने की योजनाएं चला रही है। जबकि पहले भाजपा खुद दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाओं की मुखर आलोचना करती थी, मगर चुनाव आते ही उसने भी आम आदमी पार्टी को उसी के दांव से पटखनी देने का फैसला कर लिया और उसमें उसे कामयाबी भी मिली। दिल्ली सरकार के पास शासन क्षेत्र सीमित है, उसे केंद्र के साथ तालमेल बिठा कर ही विकास योजनाओं पर आगे कदम बढ़ाना होता है। आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच शुरू से तनातनी बनी हुई थी, जिसके बीच अपने अधिकारों को लेकर कई बार केजरीवाल सरकार को अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उपराज्यपाल से उनके रिश्ते कभी समरस नहीं रहे। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने के बाद वह खींचतान समाप्त हो जाएगी और उम्मीद बनी है कि कुछ बेहतर और उल्लेखनीय काम हो सकेंगे। मगर नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम न होंगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो काम किए हैं, उससे बेहतर काम करके दिखाना होगा। फिर शहर की साफ-सफाई, जलभराव आदि जैसी समस्याओं से निपटना हर वर्ष की चुनौती है। नगर निगम के साथ किस तरह तालमेल बिठा कर वह इन मसलों को हल करने का प्रयास करेगी, उसी आधार पर उसका जनाधार मजबूत हो सकता है।

आम आदमी पार्टी की साख को सबसे अधिक नुकसान कथित शराब घोटाले की वजह से हुआ। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। पार्टी लगातार दलील देती रही कि उसके नेताओं को झूठे आरोप में फंसाया गया है, मगर वह लोगों के गले नहीं उतरी। उन्होंने दागी नेताओं को शिकस्त दी। इन नतीजों से यह भी जाहिर हुआ है कि भाजपा के काम पर लोगों का भरोसा कमजोर नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों से अधिक मुफ्त की योजनाओं का शोर सुनाई दिया।

सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट से भारत निर्माण को मिलेगी गति

चरण सिंह

आम बजट 2025 एक सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट है। यह कई मायने में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी भी है। खासकर ताजा बजट प्रस्तावों के माध्यम से मध्यम वर्ग को जो भारी कर राहत प्रदान किया गया है और आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपया तक कर दिया गया है, उससे अर्थव्यवस्था को विभिन्न कोणों से मजबूती मिलने के आसार प्रबल हैं। कुल मिलाकर यह आम आदमी का बजट है, जो गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों और नारी शक्ति को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है।

सच कहा जाए तो यह आम बजट विकसित भारत यानी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है, जिसमें किसानों, गरीबों के साथ-साथ मध्यम वर्ग पर भी ध्यान दिया गया है। वहीं, महिला और बच्चों की शिक्षा, उनके पोषण व स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। इस बजट में स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक, यानी कि अर्थव्यवस्था की समुन्नति के हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। इस प्रकार यह बजट मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का व्यापक रोडमैप है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। इसके माध्यम से उन्होंने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। जिससे आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने जा रहा है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है, जो बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा।

आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट उसके ठीक उलट है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे...इस बात की चिंता करता है। इस बजट में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण

कदम उठाए गए हैं। विशेष कर यह बजट देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।

यूँ तो बजट में हर तरह से रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, फिर भी मैं उन सुधारों की चर्चा करना उचित समझता हूं जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि शिप बिल्डिंग निर्माण सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। वहीं, देश में पर्यटन विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए पहली बार होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर होटल बनाए जाएंगे। इससे आतिथ्य क्षेत्र को ऊर्जा मिलेगी, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है।

वहीं, इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारत मिशन' शुरू किया गया है। इसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। वहीं, इस बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति का आधार बनेगी। किसान क्रेडिट कार्ड' की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी, जिससे उन्हें और मदद मिलेगी।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी, 2025, दिन शनिवार को संसद में बजट पेश किया, जो उनका लगातार 8वां बजट था। यह बजट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप रहा। क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये सालाना तक की इनकम को आयकर के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया। इससे नौकरीपेशा वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा होगा।

वहीं, उन्होंने किसान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। स्वास्थ्य और रोजगार पर हमारा खास ध्यान है। युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने दुनियाभर का ध्यान आकर्षित किया है। इस दौरान भारत की क्षमता को लेकर विश्वास बढ़ा है। इसी कड़ी में अब बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी शुल्क कम करेंगे। एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख की गई है। डेयरी और फिशरी के लिए अब पांच लाख तक का लोन दिया जाएगा। इससे इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने, एमएसएमई को समर्थन देने, रोजगार आधारित विकास को सक्षम करने, लोगों की अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। यह बजट सरकार की राजस्व और व्यय रणनीति के लिए एक सामान्य रोड मैप प्रदान करता है। बजट 2025 युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित है।

वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि यह बजट सरकारी प्रयासों को जारी रखता है- विकास में तेजी लाने के लिए, सुरक्षित समावेशी विकास के लिए, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। आम बजट में जिन विषयों पर फोकस किया गया, उनमें मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, एमएसएमई को समर्थन रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना प्रमुख हैं।

वहीं, लोगों की अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करना और निर्यात का समर्थन करना भी शामिल हैं। इस बजट में नवप्रवर्तन का पोषण व पीएम धन्य-धान योजना की घोषणा की गई है। वहीं, स्टार्टअप की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई। इस बजट में 5 नए परमाणु रियक्टर बनाने की घोषणा क्रांतिकारी

कदम है। वहीं, मुद्रा योजना में होम स्टे के लिए योजना, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिये जाने का सबको लाभ मिलेगा। वहीं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई। जबकि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। वहीं, वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई। जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है।

इस बजट में प्रत्येक प्रशिक्षु को 12 महीनों के लिए वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से परिचित कराया जाएगा और उन्हें ₹5,000 का भत्ता और ₹6,000 की एकमुश्त सहायता मिलेगी। वहीं, श्रमिकों, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास यानी सरकार ने लोगों के सिर पर छत सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, व्यवहार्यता अंतर निधि और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा दी जाएगी।

कार्यबल में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। सरकार क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात सहायता मिशन शुरू करेगी। मिशन को वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। निर्यात सहायता मिशन विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग समर्थन और एमएसएमई को समर्थन तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

कुल मिलाकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोक कल्याणकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि, वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की। वे हैं- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ये इतने सारे इंजन हैं कि बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा लगता है कि बजट में बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ यानी आंध्र

प्रदेश की इतनी बेरहमी से अनदेखी क्यों की गई?'

वहीं, कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने कहा, 'हमें यह देखने की जरूरत है कि जो वादे पहले के बजट में किये गये थे क्या वे पूरे हुए? स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए बजट को पढ़ने की जरूरत है। बिहार को लेकर हुई घोषणाएं स्वाभाविक थीं। यह राजनीति है।' जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना?'

उधर, शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, 'राज्यों के नाम देखिए- बिहार, जहां चुनाव होने वाले हैं। केवल बिहार, बिहार, बिहार। पंजाब का कोई जिक्र नहीं था। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान पिछले 4 साल से विरोध में बैठे हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या घोषणा की, यह किसान विरोधी बजट था, जो किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई, यह दुखद है।'

जबकि राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट पिछले बजट का नकल है। गांव और गरीब विरोधी बजट है। बिहार को ना कुछ मिला है और ना केंद्र की मोदी सरकार बिहार को कुछ देना चाहती है। बजट के बहाने तेजस्वी ने एक बार फिर विशेष पैकेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिहार के स्पेशल पैकेज का पैसा कहां गया? तेजस्वी ने कहा, 'चंद्रबाबू नायडू 2 लाख करोड़ का पैकेज लेकर चले गए और बिहार को नीतीश कुमार कुछ नहीं दिला पाए। नीतीश अचेत अवस्था में हैं। वहीं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय बजट पर कहा कि, 'देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार है। इसके साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शान्ति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव हैं। इसके कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केन्द्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। किन्तु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों है? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है।'

वहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, 'बजट नहीं...पर महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम इनका कोई आंकड़ा क्यों मानें, जो लोग मरने वालों के ही आंकड़े नहीं दे सकते।' वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, 'देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए; किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया।'

आम बजट 2025: आयकर कानून के सरल होने से विवाद घटेंगे

नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट, सहज, सरल और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है।

राहुल अग्रवाल

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को 64 साल पुराने आयकर कानून-1961 के सरलीकरण और इसमें चले आ रहे बेवजह के प्रविधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स बिल-2025 पेश कर दिया। 622 पन्नों के इस विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं। जबकि आयकर कानून-1961 में 1647 पन्ने और 819 धाराएं रही है। इस विधेयक में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर करदाताओं के लिए इसे आसान और पारदर्शी बनाया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट, सहज, सरल और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। निश्चित ही नये आयकर कानून से टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता के नए दौर की शुरूआत होगी, यह आयकर कानून का नया सूरज है, जो जटिलताओं एवं पेचिदगियों की जगह सरलता एवं सहजता की रोशनी बनेगा।

मौजूदा आयकर कानून की तुलना में नया आयकर कानून शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफी छोटा है, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं। एक्ट के अलग-अलग चैप्टर भी 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं, नए कानून में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि लोग आसानी से आयकर के नियम समझ सकें और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए। यह बिल आयकर प्रावधानों को सरल और आसान बनाने के बड़े मकसद से जुड़ा है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों में दिख सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रारंभ से ही कम-से-कम कानूनों एवं सरल-व्यवस्था के हिमायती रहे हैं।

दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में आर्थिक क्रांति का शंखनाद अनेक मोर्चे पर हो रहा है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बदली है बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल चुकी है। 1961 में बने आयकर कानून में बदलती जरूरत के मुताबिक नए-नए संशोधन होते रहे, जिससे इसकी जटिलता बढ़ती चली गई। यह जटिलता न केवल करदाताओं

को उलझन में डालती थी बल्कि कानूनी प्रावधानों की कई तरह से व्याख्या अनेक उलझने एवं विवाद खड़ा करती रही है। इन जटिल होती परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि अपने देश में टैक्स को लेकर विवाद लगातार बढते.गये। इन लगातार बढ़ते विवादों के कारण ही इसे दुनिया की टैक्स विवादों की राजधानी कहा जाने लगा। खासकर पिछले करीब डेढ दशक में यह ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। नौबत ऐसी आ गई कि 2023-24 तक टैक्स संबंधी मुकदमों में विवादित रकम बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसका करीब 87 प्रतिशत हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा है। संभावनाएं हैं एवं सराहनीय भी है कि नये कानून के लागू होने से विवाद भी कम होंगे एवं जनता भी राहत की सांस लेगी। निश्चित ही यह कदम स्वागतयोग्य है। इस कानून को लाकर मोदी सरकार और विशेषतः वित्तमंत्री ने अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन किया है।

आयकर कानून-1961 की जटिलताओं के कारण विवादों का अंबार लगा रहा है। जबकि आयकर विभाग को इन विवादों से कोई फायदा भी नहीं होता है क्योंकि इनमें जीत का उसका रेकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) की ओर से 34 देशों में टैक्स विवादों पर हुई एक स्टडी के मुताबिक 2015 में भारत में टैक्स विभाग को महज 11.5 प्रतिशत मामलों में ही जीत मिली थी। ओईसीडी देशों का औसत इस मामले में 65 प्रतिशत है। अवश्य ही यह स्थिति भारत के लिये चिन्ताजनक रही है। अब इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो नए आयकर कानून से कर संहिता अधिक सरल हो जाएगी और वह आयकर अधिकारियों के साथ आयकरदाताओं को भी राहत प्रदान करेगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि आयकरदाताओं को जटिल नियमों के साथ आसानी से समझ न आने वाली भाषा से छुटकारा मिले।

देश में ऐसी सरल कर प्रक्रिया की अपेक्षा रही है कि कोई भी आदमी कर चुकाने के मामले में जमीनी और कागजी, दोनों ही स्तरों पर आत्मनिर्भर हो। नया कानून इस बड़ी अपेक्षा की पूर्ति करते हुए बड़ी परेशानियों से मुक्ति की राह प्रशस्त कर रहा है। ऐसे में चाहे असेसमेंट ईयर के बदले टैक्स ईयर जैसी शब्दावली तय करने की बात हो या सैलरी डिडक्शन से जुड़े तमाम प्रावधानों को एक सेक्शन में रखने की या खेती से जुड़ी आमदनी संबंधी प्रावधानों पर स्पष्टता लाने की, प्रस्तावित बिल सही ढंग से अमल में आए तो यह देश की टैक्स व्यवस्था को मजबूती देने के साथ नया भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को भी बदल देगा। चूंकि आयकर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया है, इसलिए यह आशा की जाती है कि वहां उस पर व्यापक एवं स्वस्थ विचार-विमर्श के दौरान उसे वास्तव में सरल रूप देने में मदद मिलेगी। इस अपेक्षा के साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोग स्वेच्छा से आयकर देने को प्रेरित हों और उनके मन में किसी तरह का भय न रहे।

यह भी समय की मांग है कि सरकार आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने के उपाय करे। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में डेढ सौ करोड की आबादी वाले देश में आयकर देने वालों की संख्या चार करोड़ से भी कम है। इनमें मुख्यतः वे ही हैं, जो नौकरीपेशा हैं। आयकर विभाग को इतना चुस्त एवं दुरस्त करने की जरूरत है कि जो समर्थ होते हुए भी आयकर नहीं देते हैं, ऐसे लोगों का पता लगाये। आखिर जो संपन्न किसान एक सीमा से अधिक आय अर्जित करते हैं, उन्हें आयकर के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? इसकी अनदेखी नहीं की जाए कि कृषि आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने के नियम का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। बहुत से लोग काफी समय तक दवा के स्थान पर बीमारी ढोना पसन्द करते हैं पर क्या वे जीते जी नष्ट नहीं हो जाते? खीर को ठण्डा करके खाने की बात समझ में आती है पर बासी होने तक ठण्डी करने का क्या अर्थ रह जाता है? समर्थ लोगों को स्वैच्छा से आयकर देने के लिये तत्पर होना चाहिए।

देश में आयकर का विषय विवादों से घिरा रहा है। अभी भी कुछ अर्थशास्त्री आयकर को दोहरा एवं गैर-जरूरी कराधान मानते हैं। लम्बे समय से ऐसे स्वर भी उभरते रहे हैं कि एक आम आदमी लगभग हर वस्तु और सेवा के लिये कर चुकाता है तो फिर उससे आयकर वसूलने की जरूरत क्यों है? भविष्य में इस पर भी सकारात्मक चिन्तन की अपेक्षा है।

एक और बड़ी विसंगति का सामना आयकरदाता करता रहा है कि उसे आयकर विभाग हर मोर्चे पर सन्देह एवं शंका की नजर से देखता है। इसलिये जितना आवश्यक आयकर संबंधी नियम-कानून सरल करना है, उतना ही इस बात की अपेक्षा है कि आयकर विभाग लोगों से अनावश्यक रूप से न तो सवाल-जवाब करे और न ही किसी भूल-चूक पर उन्हें तंग करे। यह तब संभव होगा, जब आयकर अधिकारी आयकरदाताओं को संदेह की दृष्टि से देखना बंद करेंगे। उन्हें यह भी समझना होगा कि आयकर बचाने के उपाय अपनाने का मतलब कर चोरी करना नहीं होता। आयकर विभाग को उन कारणों का निवारण भी करना होगा, जिनके चलते लोग आय छिपाने के जतन करते हैं। इसी के साथ ऐसी भी व्यवस्था करनी होगी, जिससे आयकर का आकलन करने और उसकी वसूली में भ्रष्टाचार न होने पाए। आयकर विभाग को लोगों के विश्वास का उपभोक्ता नहीं अपितु संरक्षक बनना होगा। निश्चित ही नया आयकर कानून भारत की कर प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इससे करदाताओं को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आसानी होगी, कर प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 8.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक बजट

प्रवीण चौधरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट आज गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। यह प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

बजट में प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है।

प्रदेश सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया

योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

बजट में तकनीकी हब बनाने के लिए सरकार का कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी' की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्र शालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रदेश के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।

बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से 'जीरो पॉवर्टी अभियान' शुरू किया है

वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ह्यजीरो पॉवर्टी अभियानह्ल शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।

सनातन, आस्था व विकास को समर्पित योगी सरकार का बजट

विशेषज्ञों का मानना है कि यह युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। बजट में एमएसएमई, नई तकनीक, एआई व साइबर सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। नए एक्सप्रेस- वे बनने से दूर की यात्रा आसान होगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए सनातन को समर्पित करते हुए सामाजिक सरोकारों वाला व्यापक बजट प्रस्तुत किया है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग तथा जीवन के हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। सर्वसमावेशी होने के कारण छात्र, किसान, व्यापारी, महिलाएं, विषय विशेषज्ञ और उद्योगपति सभी इस बजट की सराहना कर रहे हैं। बजट में धर्मस्थलों के विकास व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। प्रदेश सरकार के बजट में हर उस क्षेत्र तक पहुंच बनाने का प्रयास किया गया है जो आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बजट में अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण

संजीव कुमार

का प्रारम्भ महाकुंभ के आयोजन से किया और फिर धर्मस्थलों के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर व मां विन्ध्यवासिनी कॉरिडोर की स्थापना के बाद सरकार मथुरा में श्री बांकेबिहारी जी महाराज मंदिर, मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण करायेगी। इसके लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ और निर्माण के लिए 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थपना के लिए 100 करोड़ रु. खर्च किये जायेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहले ही 25 करोड़ बजट के साथ पांच एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के केंद्र में वैदिक पर्यावरण, वैदिक गणित, वैदिक विधिशास्त्र, वैदिक योग विज्ञान, वैदिक वन औषधियां वनस्पति आदि पाठ्यक्रम होंगे। यहां पर बड़े वैदिक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया जाएगा, साथ ही वेदशाला, वैदिक संग्रहालय, तारा मंडल, संगोष्ठी कक्ष बनाये जाएंगे। केंद्र में गुरुकुल व आधुनिक पद्धति के अंतर्गत कक्षाएं बनायी जायेंगी।

मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के तहत 400 करोड़ रु. खर्च किये जायेंगे। अयोध्या में पर्यटन अवस्थापना विकास के लिए 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मथुरा में 125

करोड़ नैमिषारण्य मे 100 करोड़ चित्रकूट में 50 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। मिजार्पुर में मां विन्ध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ व जनसुविधा स्थलों का विकास किया जायेगा। संरक्षित मंदिरो के जीर्णोद्वार के लिए 30 करोड़, महाभारत सर्किट के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़, जैन सर्किट के विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी धन का प्रावधान किया गया है। गुरुस्वामी हरिदास की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय संगीत समारोह के लिए एक करोड़ और अयोध्या में जिला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के लिए भी एक करोड़ की धनराशि रखी गई है। योगी सरकार ने वर्तमान बजट से धार्मिक पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लौ प्रदीप्त की है।

बजट में महापुरुषों पर भी ध्यान दिया गया है जिसके अंतर्गत बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जायेगा। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर दो चर्मोद्योग स्थापित किये जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेत्र पर 251 करोड़ रु. की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना होगी। प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालाय स्थापित किये जायेंगे।बजट में युवाओं और छात्राओं को आकर्षित करने के लिए भी प्रावधान किये गये हैं। अब प्रदेश की हर मेधावी छात्रा को स्कूटी दी जायेगी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रु. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है। यही नही माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनेंगे।

प्रदेश के बजट में युवा उद्यमी अभियान के लिए भी 1000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के व्यापक विकास का विस्तृत खाका बजट में रखा गया है। बजट के अनुसार अवध में केवल अयोध्या का ही विकास नहीं हो रहा अपितु अवध के हर जिले के विकास की अद्भुत पटकथा लिखी जायेगी। बजट के प्रावधान इस प्रकार से बनाये गये हैं कि एक प्रकार से यह आगामी 25 वर्षों के विकास का रोडमैप प्रस्तुत कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में चार नए एक्सप्रेस वे के निर्माण से तीन तीर्थस्थलों काशी, प्रयागराज व हरिद्वार की यात्रा सरल हो जायेगी। चार नए एक्सप्रेस वे के लिए बजट में 1,050 करोड़ रु. की व्यवस्था कर दी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिजार्पुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जायेगा। इससे इस क्षेत्र के विकास की गति दोगुनी हो जायेगी व धार्मिक पर्यटन और बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। बजट में एमएसएमई, नई तकनीक, एआई व साइबर सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। नए एक्सप्रेस- वे बनने से दूर की यात्रा आसान होगी। नए एक्सप्रेस वे बनने से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एआई सिटी बनाने की घोषणा से स्टार्टअप और आईटी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।प्रदेश का बजट इंफ्रास्टक्चर को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगारों को रोजगारपरक बनाने वाला बजट है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। बजट में एमएसएमई, नई तकनीक, एआई व साइबर सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। नए एक्सप्रेस- वे बनने से दूर की यात्रा आसान होगी। नए एक्सप्रेस वे बनने से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एआई सिटी बनाने की घोषणा से स्टार्टअप और आईटी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।प्रदेश का बजट इंफ्रास्टक्चर को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगारों को रोजगारपरक बनाने वाला बजट है। यह बजट राज्य की तकनीकी प्रगति औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। प्रदेश के बजट में सड़क राजमार्ग के चौड़ीकरण पर भी पर्याप्त फोकस किया गया है। इसका सर्वाधिक लाभ राजधानी लखनऊ व उसके आसपास के जिलों व कस्बों आदि को मिलेगा। मोहनलालगंज -गोसाईगंज होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे निकल रहा है इसका चौड़ीकरण किया जायेगा। इसी तरह बनी से ही एक रोड हरौनी होते हुए मोहन को निकली है इसे भी दो लेन का किया जायेगा। यह बजट समग्र विकास वाला बजट है। इसमें किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। बजट में कोरोना काल में अनाथ 1430 बच्चों को आर्थिक सहायता प्रादन करने के लिए 250 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। बजट में सात सरोकारों पर्यावरण संरक्षण ,नारी सशक्तीकरण, जल सरंक्षण, सुशिक्षित समाज, जनसंख्या नियोजन, स्वस्थ समाज, गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट का 23 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण अनुकूलन पहली पर खर्च किया जायेगा। सरकार वनीकरण, कार्बन अवशोषण और पयार्वरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण को और अधिक बढ़ावा देने जा रही है। इसी प्रकार सुशिक्षित समाज के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जायेगा। इसी प्रकार स्वस्थ समाज के लिए कुल बजट का छह प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होगा। प्रदेश में जलसंरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 4500 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन के लिए 90 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें तालाबों का जीर्णोद्धार तथा निमार्णा भी शामिल है। जनसंख्या नियोजन के अंतर्गत युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड स्थापित किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए भी 250 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में सभी मंडल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जायेगा। ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भवन निर्माण की कार्ययोजना पर भी कार्य किया जायेगा। यह बजट सभी वर्गो के लिए है अर्थात समग्रता पर आधारित है जिससे इसकी छाप वैश्विक होने जा रही है। प्रदेश की सुदृढ़ होती कानून-व्यवस्था से देश विदेश के निवेशक भी अब आकर्षित हो रहे हैं तथा प्रदेश में भारी निवेश भी हो रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान बजट से 2050 तक का लक्ष्य साधने का प्रयास किया है यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जिसका सीधा अर्थ यह हे कि विकास का लक्ष्य और पैमाना बहुत बड़ा है। यह तुष्टिकरण वाला बजट नहीं अपितु सभी के संतुष्टिकरण वाला बजट है।

उत्तर प्रदेश 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा: सीएम योगी

विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिए सवालों के जवाब

इंद्रेश शर्मा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आई थी, तब राज्य की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपये थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 27.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भारत को विकसित राष्ट्र नहीं मानते, वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि पर भी सवाल उठाते हैं, भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच चुकी है और 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत 2017 से पहले बेहद खराब थी, लेकिन आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, बल्कि अपनी उपज का डेढ़ गुना मूल्य पा रहा है।

उन्होंने बताया कि धान की खेती में किसानों को प्रति क्विंटल 2300 रुपये मिल रहे हैं, जबकि लागत 1100 रुपये आती है। इसी तरह गेहूं पर भी सरकार किसानों को दोगुना मूल्य दे रही है।

गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बन चुका है और एथेनॉल उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर है।

तेजी से बढ़ रही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्थाः सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर की मासिक समीक्षा की जाती है और मुख्यमंत्री स्वयं तिमाही समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। कई उद्योगों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इस निवेश से 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सीएम योगी ने कहा कि यह वही प्रदेश है जहां सीडी रेशियो 44 प्रतिशत था। आज यह 60 प्रतिशत क्रॉस कर चुका है। यह दशार्ता है कि उत्तर प्रदेश का पैसा आज उत्तर प्रदेश में लग रहा है। यह रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि पिछले पंच वर्षीय योजना के अंदर उत्तर प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जिसने बैंको से सबसे अधिक लेन देन की है। जनधन अकाउंट उसके उदाहरण हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिनका कभी बैंक में अकाउंट नही था आज उनके अकाउंट में लाखों रुपये उन बैंको में जमा है। आज उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रूपया उन बैंकों में जमा है इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की क्रय करने की सामर्थ भी और जमा करने की सामर्थ भी बड़ी है यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के कारण संभव हो पाया है।

उत्तर प्रदेश बनेगा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाः सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबन के दिशा में जो कार्य हुए हैं उसमें अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भार्ती अनिवार्य रूप से की गई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोगों लगता है कि यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नहीं हासिल कर पाएगा तो यह आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को जिसको आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया था, यह देश की छठी-सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, इन संसाधनों का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश छठी-सातवीं अर्थव्यवस्था से उभरकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालितः योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित करने वाला राज्य बन चुका है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह सेक्टर बदहाल हो गया था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया गया। कोविड काल में वापस लौटे 40 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर उन्हें एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा गया, जिससे दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। सीएम योगी ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ह्यसीएम युवा उद्यमी योजनाह्न शुरू की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना के पहले चरण में 5 लाख रुपये और दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अब तक 96 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2023 में 65 करोड़ पर्यटक राज्य में आए और महाकुंभ में अकेले 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को जिसको देश और दुनिया आज देख रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देगा।

मुल्ला और मौलवी के बजाय हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं: योगी

डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी: सीएम योगी आदित्यनाथ

सुदामा पाल

विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता संकीर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को केवल पारंपरिक मदरसों तक सीमित नहीं रखना चाहती उन्हें मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साहित्यकार बनाने का अवसर भी प्रदान करना चाहती है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण से ही समाज का विकास संभव है। सीएम योगी ने कहा कि स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है। उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। उन्होंने दोहराया कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार हर बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है

सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है, जिससे वे केवल मजहबी शिक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनें। सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े और राष्ट्र के विकास में योगदान दे। बच्चे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं कोई भेदभाव नहीं करेंगे उत्तम शिक्षा मिलेगी

अच्छी शिक्षा मिलेगी आधुनिक शिक्षा मिलेगी बिना भेदभाव के मिलेगी सरकार इसके लिए दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए हर सुविधा से आच्छादित करेगी, लेकिन जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वह वहां जाएं लेकिन अच्छा साहित्यकार अच्छा वैज्ञानिक अच्छा गणितज्ञ अच्छा शिक्षक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को लाभ मिल रहा है।

डबल इंजन की सरकार ने इन सभी जनजातियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया

सीएम योगी ने विधान परिषद में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए थारू जनजाति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह जनजाति उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर और सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रदेश की जनजातियों और वंचित वर्गों की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि थारू, मुसहर, गोंड और अन्य वंचित जनजातियों के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, न उनके पास जमीन के पट्टे थे, न राशन कार्ड, न ही मकान। डबल इंजन की सरकार ने इन सभी जनजातियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

सरकार ने अगले तीन वर्षों में 13.5 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा है

सीएम योगी ने कहा कि पिछले साढ़े साथ वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने जो कदम उठाए गए हैं उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ व देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य जीवन जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों में 13.5 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ऐसे परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा और उनकी वार्षिक आय को न्यूनतम 1.25 लाख रुपये तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार पहले चरण का काम पूरा कर चुकी है और इसे आगे और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल एक ढोंग है। उन्होंने ने कहा कि वे केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। उन्होंने प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के इसे एक मिशन के रूप में लिया और व्यापक स्तर पर टीकाकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आज यह बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच केवल राजनीति तक सीमित है। वे विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया है।

नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम के मिलने लगे हैं बेहतर नतीजे

अनिल वशिष्ठ

बता दें कि भारत सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए। ये ऑपरेशन उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है।

आमतौर पर नक्सली, आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड अपने पूरे जमात के साथ भारतीय गणतंत्र के लिए चुनौती समझे जाते हैं। इसलिए सुरक्षाबलों ने 76वें गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाए हैं और एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वह तिरंगे और संवैधानिक गणतांत्रिक व्यवस्था को सच्ची सलामी है। इसलिए देशवासियों की अपेक्षा है कि सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई और अधिक तेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम उनके नापाक हौसले को तोड़ सकते हैं।

देखा जाए तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय थल या समुद्री सीमा से सटे प्रदेश हों या हमारे आंतरिक प्रदेश, यहां पर नक्सलियों, आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की मौजूदगी और उनके मार्फत जब-तब होते रहने वाली हिंसात्मक घटनाएं एक ओर जहां शासन व्यवस्था और अमनपसंद लोगों को मुंह चिढ़ाती हैं, वहीं दूसरी ओर धनी लोगों के भयादोहन का कारण भी बनती हैं। चूंकि अवैध मानव व वस्तु तस्करी, ड्रग्स सिंडिकेट, अवैध हथियारों के कारोबार, फिरौती, विवादास्पद सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त आदि से इनके तार जुड़े होते हैं, इसलिए सफेदपोश नेताओं-समाजसेवियों-कथित अधिकारियों-उद्योगपतियों आदि के माध्यम से इनके सरगना भी परस्पर मिले हुए होते हैं।

आम धारणा रही है कि इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं से इनकी गुप्त सांठगांठ रहती है! और यही इनके तार कथित राष्ट्रीय नेताओं और अर्बन नक्सलियों-अपराधियों-आतंकवादियों के सिंडिकेट तक से जोड़ते हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी सियासी कारणों के चलते इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्यों की आतंकी घटनाएं हों, या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार की नक्सली घटनाएं, या फिर बड़े महानगरों से लेकर जिलास्तरीय शहरों की अंडरवर्ल्ड वारदातें, इनके तार परस्पर जुड़े बताए जाते हैं।

कहना न होगा कि इनमें से कई राज्यों में क्षेत्रीय

दलों की मजबूती के पीछे भी इनकी राष्ट्रविरोधी सोच होती हैं, जिन्हें बरास्ता नेपाल, पाकिस्तान व चीन का भी संरक्षण हासिल होता है। वहीं, कांग्रेस समेत कई बड़े क्षेत्रीय दल भी इनके नेक्सस के समक्ष घुटने टेक चुके हैं। जबकि इन सभी बातों से उलट केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी भाजपा नीत एनडीए की सरकार और उड़ीसा-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की भाजपा प्रदेश सरकारों की संगठित अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रोत्साहित होकर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रणनीति बनाकर नक्सलियों-दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी एक झलक ताजा कार्रवाई से मिलती है।

गौरतलब है कि भारत में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता तब मिली, जब गत दिनों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), छत्तीसगढ़ के एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और ओडिशा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 14 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से की गई त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हथियार और बाकी सामग्री भी बरामद की गई जो नक्सली गतिविधियों को और बढ़ावा दे रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों के इस संयुक्त ऑपरेशन में नक्सल आंदोलन का एक प्रमुख सरगना, जयराम चलपती को ढेर किया गया। क्योंकि जयराम को नक्सली हिडमा का गुरु माना जाता था और नक्सली गतिविधियों में उसकी अहम भूमिका थी। जयराम पर 1 करोड़ रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए जयराम की तलाश एक बड़ी चुनौती थी। ऐसा इसलिए कि वह नक्सलवादी समूहों के लिए एक अहम रणनीतिक सोच के रूप में काम करता था। उसकी मृत्यु से न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा बल्कि पूरे देश में नक्सलवादी आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है।

बताया जाता है कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर जयराम और उसके साथी नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से सख्त अभियान चलाया था। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर इस सफलता पर बधाई दी और सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक और अहम कदम है। बता दें कि भारत सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए। ये ऑपरेशन उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। समझा जा रहा है कि जयराम की मौत के बाद अब नक्सलियों के मनोबल को भारी झटका लगेगा और उन्हें पुनः अपनी ताकत को संगठित करना मुश्किल होगा। सुरक्षा बलों की ये सफलता न केवल एक बड़ी सैन्य जीत है बल्कि ये देश के नागरिकों के लिए एक संदेश भी है कि नक्सलवाद का खात्मा अब बिल्कुल नजदीक है।

बता दें कि एक साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के रोडमैप को जो हरी झंडी दी थी, उसके तहत एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कुल 96 मामलों की जांच कर रही है। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और सटीक रणनीति का ही यह तकाजा है कि हाल ही में 14 नक्सली एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। उल्लेखनीय है कि एक साल पहले 21 जनवरी 2024 को गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व एवं सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी, जिसमें नक्सलवाद को खत्म करने के रोडमैप को हरी झंडी दी थी। वहीं, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के विपरीत नवनियुक्त विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस रोडमैप को अमली जामा पहनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित की, जिसका बेहतर नतीजा सबके सामने है।

गौरतलब है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाए गए अमित शाह के रोडमैप में तीन अहम बिंदू हैं। पहला, नक्सलियों के कोर इलाके में सुरक्षा बलों की अग्रिम चौकियां स्थापित कर सुरक्षा गैप को भरना, दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून का इस्तेमाल कर ईडी की मदद से नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग के स्त्रोत को पूरी तरह से बंद करना, और तीसरा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून का इस्तेमाल पर नक्सली गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ एनआईए की जांच कराकर कड़ा सजा सुनिश्चित करना। कहना न होगा कि तीनों ही फ्रंट में राज्य प्रशासन के सहयोग से बेहतरीन काम हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के बाद सुरक्षा बलों की 290 अग्रिम चौकियां स्थापित की गईं, जिनमें अकेले साल 2024 में 58 अग्रिम चौंकियां स्थापित करना शामिल हैं। वहीं, इस साल 2025 में सुरक्षा बलों की कुल 88 अग्रिम चौकियां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, राज्य सरकारें, ईडी और एनआईए ने नक्सल फंडिंग से जुड़ी 72 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है। वहीं, एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कुल 96 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 56 मामले पिछले तीन साल में दर्ज किये गए। इनमें से 77 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।

एक्सपर्ट बताते हैं कि कहने को अग्रिम सुरक्षा चौकियों का गठन छोटी बात लग सकती है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह कारगर रणनीति साबित हो रही है। क्योंकि अग्रिम सुरक्षा चौकियां बनने से उसके तीन-चार किलोमीटर के दायरे में नक्सलियों के लिए अपनी गतिविधि चलाना संभव नहीं रहता है। वहीं, दूसरी बात यह है कि इन चौकियों के सहारे सरकारी तंत्र और लोक कल्याणकारी व विकास योजनाएं भी ग्रामीणों तक पहुंच रही है। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक अबूझमाड़ से लेकर दंडकारण्य और उससे आगे तक फैले नक्सल प्रभाव वाले पूरे इलाके में हर तीन-चार किलोमीटर पर एक सुरक्षा अग्रिम चौकी स्थापित कर करने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि इन अग्रिम चौकियों का ही कमाल है कि वर्ष 2023 में जहां मात्र 50 नक्सलियों को मार गिराया गया था, वहीं उसकी तुलना में साल 2024 में 290 नक्सली मारे गए हैं। यही नहीं, इस साल 2025 में 21 जनवरी तक 48 नक्सली मारे जा चुके हैं।

इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2025 में स्थापित होने वाले नए 88 अग्रिम सुरक्षा चौकियों की स्थापना से सुरक्षा बलों के आपरेशन की ताकत में और इजाफा होगा। वहीं, अगले साल 2026 में प्रस्तावित सभी सुरक्षा चौकियों के बनने के बाद नक्सलियों के पास अपनी गतिविधि चलाने को कोई भी सुरक्षित क्षेत्र ही नहीं बचेगा। यही वजह है कि उसके बाद ही नक्सलवाद के खात्मे का एलान किया जाएगा। इससे साफ है कि अमित शाह की सटीक रणनीति ने बाजी उनके पक्ष में पलटती जा रही है, जिससे एक सफल गृहमंत्री के रूप में उनके नाम का शुमार किया जाने लगा है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों ने जो अभियान छेड़ रखा है, उसकी अनवरत कार्रवाइयों और सटीक रणनीति के कारण एक साल भीतर ही नक्सलियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि भारत सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए। ये ऑपरेशन उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है।

मुकुल शर्मा

कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों में भी पतन का दौर

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, कि अरविंद जिस तेजी से राजनीति में चमके थे उसी तत्परता से औंधे मुंह जा गिरे। अब उनका कोई भविष्य नहीं है और इसकी वजह है उनका बड़बोलापन और भरोसे की राजनीति न करना एवं उनकी अवसरवादिता।

देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उभार और कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय दलों का पतन काफी कुछ कहता है। भले ही हार से बौखलाए मोदी और बीजेपी विरोधी नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हों ? सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करते हों ? लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोधियों को अपनी राजनैतिक कमजोरी और सियासी अपरिपक्वता का अहसास नहीं है,लेकिन बार-बार पराजित हो रहे यह नेता सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी को छोड़कर देश की किसी भी राजनैतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है। इसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी,समाजवादी पार्टी,राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल,उद्धव ठाकरे की शिवसेना,शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की लम्बी चौड़ी लिस्ट हैं। अब इसमें नया नाम कट्टर ईमानरदार ह्यआम आदमी पार्टीह्ल का भी जुड़ गया है।

हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हार के लिये अभी तक ईवीएम मशीन या सरकारी मशीनरी पर किसी तरह की धांधली का आरोप नहीं लगाया है,जबकि उसी समय उत्तर प्रदेश में अयोध्या की चर्चित मिल्कीपुर विधान सभा सीट पर मिली जबर्दस्त हार के बाद समाजवादी पार्टी का प्रलाप लगातार जारी है। ऐसा ही प्रलाप कांग्रेस अध्यक्ष खरगे,नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सहित उनकी पार्टी के तमाम नेता भी करते रहते हैं। हालात यह है कि हार से बौखला कर मोदी विरोधी नेता उन्हें(मोदी) और बीजेपी को ही नहीं चुनाव आयोग,सीबीआई,ईडी जैसी एजेंसियों के खिलाफ भी भड़ास निकालते रहते हैं। यह नेता

मोदी को नीचा दिखाने के लिये देश की छवि भी खराब करने से नहीं चूकते हैं। इसमें विदेश से पढ़ाई करके आने वाले टेक्नोटेक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आईआरएस रह चुके अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता शामिल हैं तो बिहार में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भी आरोप-प्रत्यारोप वाली सियासत से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी आभा को एकदम मटियामेट कर दिया है. जो केजरीवाल 12 साल पहले यूथ आइकॉन बनकर उभरे थे, वे अब धूल में लथपथ पड़े हैं. विधान सभा में ह्यदिल्ली का मालिक मैं हूंह्य जैसे अहंकारी बयान देने वाले और हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाकर अपनी फजीहत करा चुके अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे आधे-अधूरे राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे थे मगर अब वे विधायकी भी गंवा बैठे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, कि अरविंद जिस तेजी से राजनीति में चमके थे उसी तत्परता से औंधे मुंह जा गिरे। अब उनका कोई भविष्य नहीं है और इसकी वजह है उनका बड़बोलापन और भरोसे की राजनीति न करना एवं उनकी अवसरवादिता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से अधिक भद्द राहुल गांधी की पिटी है। पिछले कई चुनावों से दिल्ली में शून्य सीटों का रिकॉर्ड

> देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की लम्बी चौड़ी लिस्ट हैं। अब इसमें नया नाम कट्टर ईमानदार 'आम आदमी पार्टी' का भी जुड़ गया है।

राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम दर्ज है।

अरविंद केजरीवाल की तरह ही नेताजी मुलायम सिंह यादव की राजनैतिक विरासत संभाले हुए अखिलेश यादव की है। 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपनी जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, जबकि अनुभव के नाम पर अखिलेश खाली हाथ थे। इसके बाद अखिलेश यादव अपने दम पर भले ही राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाये हों, लेकिन उनके बड़बोलेपन और अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की महारथ के चलते खूब नाम कमा रहे हैं।विवादित बयानबाजी की बात की जाये तो अखिलेश यादव अपने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का नया राजा कहकर प्रभु श्रीराम और उनके भक्तों का उपहास उड़ाने के चक्कर में खुद फजीहत करा बैठते हैं। उन्हें ट्रॉफी की तरह अपने साथ लेकर घूमते थे, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश अपने होश खो बैठे हैं। सपा नेता हार से इतना बौखला गये हैं कि पार्टी के महासचिव प्रो रामगोपाल यादव तो यूपी के सरकारी अधिकारियों को ही नसीहत देने लगे हैं कि वह मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश सुनने की बजाये उन्हें नसीहत दें। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव हताशा में डूबते जा रहे हैं। रामगोपाल तो अयोध्या में रामलला के मंदिर को भी बेकार कह चुके हैं। सपा के तमाम नेता महाकुंभ में कथित अव्यवस्था को लेकर भी लगातार सीएम पर हमलावर हैं, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को हासिल क्या हो रहा है, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।क्योंकि समाजवादी पार्टी का पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मिल्कीपुर में तो सपा को यादवों तक का वोट नहीं मिला।

क्या जघन्य अपराधियों की न सुनी जाये पैरोल की अर्जी?

कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को खतरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर गलत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं।

अजीत शर्मा

पैरोल सुधार और पुनः एकीकरण पर आधारित है, लेकिन जब इसका उपयोग गंभीर अपराधों के लिए किया जाता है, तो यह नैतिक और कानूनी दुविधाएँ पैदा करता है। मानवाधिकारों और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, भले ही न्याय दंड और रोकथाम की मांग करता हो। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण कदम पैरोल है। यह कैदियों को समाज में पुनः एकीकृत करने में सहायता करने के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का विचार है। यह कैदी की सामाजिक पुनर्प्राप्ति के लिए एक उपकरण से अधिक कुछ नहीं है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर गलत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं। चूँकि हमारी जेलें अहिंसक अपराधियों से सचमुच भरी हुई हैं, इसलिए पैरोल से जेल में बंद लोगों को अपने प्रियजनों के साथ अपनी सजा के बचे हुए हिस्से को पूरा करने का मौका मिलता है, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उन पर कड़ी नजर रहती है। यह हर दिन लाखों रुपयों की टैक्स बचत करता है और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है। बहुत कम बार आप किसी हिंसक अपराधी के बारे में सुनते हैं जो पैरोल पर रिहा हुआ और फिर एक और हिंसक अपराध करने लगा।

ज्यादातर हिंसक अपराधी किसी भी मामले में अपनी सजा का कम से कम 85% हिस्सा पूरा करते हैं। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि पैरोल से पीड़ितों और उनके परिवारों की न्याय की भावना कमजोर हो सकती है। आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ मजबूत रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम बनाए रखने के लिए, 2012 के निर्भया मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को खतरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। बार-बार अपराध करने के कारण, 2013 के शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार मामले

के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। राजनीतिक प्रभाव से न्याय में विश्वास को नुकसान हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप पैरोल की मंजूरी मिलती है जो वारंटेड नहीं होती है।

टी. पी. चंद्रशेखरन हत्या मामले में पैरोल कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के कारण दी गई थी। इन अपराधों में शामिल क्रूरता और पूर्व-योजना के कारण, सुधार चुनौतीपूर्ण है। 2018 के कठुआ बलात्कार मामले ने स्पष्ट कर दिया कि दया से रहित कठोर दंड की आवश्यकता है। भारतीय न्यायालयों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को संतानोत्पत्ति और विवाह के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है। हालाँकि, चूँकि विवाह के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इस आधार पर पैरोल देने से समलैंगिक कैदियों के समानता के अधिकार से समझौता होता है।

सभी कैदियों के लिए समानता और समावेशिता की गारंटी देने के लिए, न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत अंतरंगता के अधिक सामान्य अधिकार से पैरोल को जोड़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला नियम (2015), कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, का एक प्रमुख घटक सुधार है। पैरोल एक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार, जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कई फैसलों में जोर दिया है। सामान्य प्रतिबंध होने के बजाय, व्यवहार मूल्यांकन के आधार पर पैरोल दी जानी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के पुनर्वास के परिणामस्वरूप 2023 में महाराष्ट्र में पुनरावृत्ति में कमी आई। पैरोल अनुरोधों का मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा पहले से ही योग्यता के आधार पर किया जाता है, जिससे सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिलती है।

हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह (2003) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पैरोल निष्पक्ष मानकों के अनुसार दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास द्वारा किया जा सकता है, यदि सुधार प्रदर्शित किया जाता है। श्रीहरन (2015) के अनुसार, किसी को पैरोल से पूरी तरह से वंचित करना असंवैधानिक है। नॉर्वे जैसे देशों में धीरे-धीरे पुनः एकीकरण पर जोर देकर, यहाँ तक कि जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के लिए भी पुनः अपराध दर कम हो गई है। पुनर्वास न्याय के अपने मॉडल की बदौलत नॉर्वे में दुनिया में पुनरावृत्ति की सबसे कम दरें हैं।

जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव से पैरोल प्रशासन की प्रभावशीलता बाधित हुई है। कार्यक्रम के लक्ष्य से नियमित रूप से समझौता किया जाता है और कई अनुचित अपराधियों को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में पैरोल दी जाती है। पैरोल के सम्बंध में, एक अच्छी तरह से परिभाषित न्यायिक नीति आवश्यक है और किए गए कार्यकारी कर्तव्यों की अदालतों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे कानून निमार्ताओं के लिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने का समय आ गया है। इन बदलावों में कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रगतिशील तरीके से पर्यवेक्षित रिहाई प्रणाली को लागू करने के लिए मजबूत दिशा-निर्देश बनाना, लगातार पैरोल कानून बनाकर यह साबित करना कि यह पुनर्वास के लिए एक प्रभावी उपकरण है और भारत में पैरोल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जाँच और संतुलन स्थापित करना शामिल होना चाहिए। सरकार को जेलों में भीड़भाड़ के बारे में चिंतित होना चाहिए और उन्हें तुरंत इस पर गौर करना चाहिए। भयानक अपराधों के लिए पैरोल को सीमित करते समय न्याय, निवारण और पुनर्वास सभी पर विचार किया जाना चाहिए। सख्त न्यायिक निगरानी के साथ पारदर्शी, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापक प्रतिबंधों के बिना सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिक निष्पक्षता की गारंटी दी जा सकती है। पैरोल एक ऐसी चीज है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि स्पष्ट है।

दिल्ली की किस्मत 'रेखा गुप्ता' से एनसीआर की अपेक्षाएं

एन के शर्मा

लिहाजा, अब यह रेखा गुप्ता पर निर्भर करेगा कि हरियाणा-उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकारों को साधकर वह दिल्ली-एनसीआर वासियों के दूरगामी हित कितने महत्वपूर्ण कदम उठा पाती हैं। वहीं यदि वह राजस्थान और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों को भी साध लें तो दिल्ली-एनसीआर वासियों का ज्यादा भला कर पाएंगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से न केवल दिल्ली वासियों बल्कि एनसीआर के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के इतिहास में संभवतया यह पहला मौका है जब दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तरप्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। चूंकि दिल्ली और एनसीआर के शहरों यथा-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत आदि में चोली-दामन का सम्बन्ध बन चुका है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से सबकी सकारात्मक अपेक्षाएं रहती आई हैं।

लिहाजा, अब यह रेखा गुप्ता पर निर्भर करेगा कि हरियाणा-उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकारों को साधकर वह दिल्ली-एनसीआर वासियों के दूरगामी हित कितने महत्वपूर्ण कदम उठा पाती हैं। वहीं यदि वह राजस्थान और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों को भी साध लें तो दिल्ली-एनसीआर वासियों का ज्यादा भला कर पाएंगी। ध्रुवसत्य है कि जब लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें किसी नेता के एजेंडे में शामिल हो जाती हैं तो दोनों का संतुलित विकास होता है। ऐसे में यदि भाजपा और उसके तीनों-चारों मुख्यमंत्री जनहित में 'ग्रेटर दिल्ली' बनाने की पहल करे तो एनसीआर वासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि ऐसा होने से जहां गाजियाबाद-गौतमबुद्धनगर के लोगों को लखनऊ-प्रयागराज-कानपुर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, वहीं फरीदाबाद-गुरुग्राम-रोहतक-सोनीपत के लोगों को चंडीगढ़ जाने से मुक्ति मिलेगी।

वहीं, जो लोग अब तक यह कहते आए हैं कि दिल्ली का न अपना मौसम है, न पानी है, उनकी यह शिकायत भी दूर हो जाएगी। क्योंकि ग्रेटर दिल्ली के पास अपना मौसम और अपना पानी दोनों हो जाएगा। निर्बाध विद्युत आपूर्ति में भी कोई बाधा नहीं आएगी। सड़कें चकाचक हो जाएंगी। यही नहीं, ग्रेटर दिल्ली बनने से यहां की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा सीटें बढ़ेगी, नगर निगम का आकार बढ़ेगा और यहां विधान परिषद के गठन की भी बात बढ़ेगी। इसके अलावा, यहां न केवल

अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा, बल्कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के संतुलित विकास में भी मदद मिलेगी।

इसलिए भले ही हरियाणा सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार या राजस्थान सरकार ग्रेटर दिल्ली बनाने के लिए अपने विकसित शहर व जनपद देने को राजी न हों, लेकिन दिल्ली-एनसीआर वासियों के भावी हितों के मद्देनजर केंद्र सरकार को इसके लिए खुले दिल से विचार करना चाहिए। यह मुद्दा कोई कपोलकल्पित बात नहीं है, बल्कि जब तब चुनावों में उठता भी आया है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनवाने के पीछे लोगों के जेहन में भी यह बात रही है। चूंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, इसलिए ये वाला फॉमूर्ला यहां भी लागू होना चाहिए।

यदि ऐसा होता है तो दिल्ली की दो बड़ी समस्याओं- यमुना नदी प्रदूषण और वायु प्रदूषण का भी ठोस समाधान निकल पाएगा। यहां के उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि और जनसंख्या की किल्लत भी महसूस नहीं होगी।

एक सीजीएसटी और चार एसजीएसटी से भी उद्यमी बच जाएंगे। चूंकि दिल्ली को छोटा हिंदुस्तान करार दिया जाता है, इसलिए इसका दायरा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक विकास में भी यहां मदद मिलेगी। यदि आप देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर नजर डालेंगे तो अधिकांश जगहों पर भाजपा और एनडीए की सरकार मिलेगी। इसलिए उनसे तालमेल बिठाकर भी ग्रेटर दिल्ली के सपने को साकार किया जा सकता है।

वहीं, दिल्ली-एनसीआर के कूड़े-कचरों का भी सही समायोजन हो पाएगा। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को 100-150 किलोमीटर दूर ले जाने में भी मदद मिलेगी।वाकई, दिल्ली-एनसीआर का भौगोलिक क्षेत्र जितना बड़ा है, यदि उसे ग्रेटर दिल्ली में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस दिल्ली प्रदेश के विकास में आशातीत उन्नति होगी।

ऐसा इसलिए कि अमूमन यहां के लोग एक दिन में दो-तीन-चार-पांच प्रदेशों का दौरा कारोबारी, राजनीतिक, समाजसेवा या व्यक्तिगत कारणों से करते हैं, इससे उन्हें सभी राज्यों को अलग-अलग टैक्स/टोल टैक्स आदि भी देना पड़ता है, जिससे यहां के उत्पाद महंगे हो जाते हैं।

यदि ऐसा हुआ तो यहां के लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि एनसीआर के शहरों को सलीके से लूटने के लिए इनके इनके प्रदेश मुख्यालयों में गिरोह सक्रिय रहता है। लिहाजा ग्रेटर दिल्ली बनने से इस घटिया मानसिकता से भी मुक्ति मिलेगी। चूंकि आप और कांग्रेस से चुनावी प्रतिस्पर्धा में भाजपा ने कई फ्रीबीज की घोषणाएं की हैं, इसलिए उनको भी एक एक करके पूरा करवाने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के कंधों पर होगी।

दिल्ली में सड़कों का निर्माण, शिक्षा व जनस्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, झुग्गी-झोपड़ियों का विकास, अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में पार्क, सामुदायिक भवन, शौचालय, पेयजल आदि जनसुविधाओं की बहाली पर भी रेखा गुप्ता सरकार को तुरंत फोकस करना होगा, क्योंकि दिल्ली के मतदाता जागरूक बहुत हैं। चूंकि रेखा गुप्ता हरियाणा मूल की भाजपा नेत्री हैं, अग्रवाल वैश्य समाज से आती हैं, प्रगतिशील महिला हैं, आरएसएस-भाजपा के लोगों को साथ लेकर चलती आई हैं, मोदी-शाह के एजेंडे के प्रति ततपर रहती आई हैं, इसलिए नवनिर्वाचित विधायक होने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मौका दिया है।

कहना न होगा कि उन्हें तीन बार निगम पार्षद बनने, डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष रहने, एमसीडी मेयर का चुनाव लड़ने और पार्टी में विभिन्न पदों पर सक्रिय रहने का गौरव हासिल है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि वह उन्हें निराश नहीं करेंगी। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में उन्होंने पार्टी के जितने बड़े-बड़े कद्दावर नेताओं को धराशायी किया है, उससे स्पष्ट है कि साधारण दिखती हुई भी वो असाधारण शख्सियत रखती हैं। इसलिए दिल्ली-एनसीआर के सपनों ग्रेटर दिल्ली को भी साकार कर सकती हैं, यदि वह ठान लें तो।

'मोदी मंत्र' से दिल्ली के अभेद्य दुर्ग को आखिरकार जीत ही गयी 'भाजपा'

दिल्ली की चुनावी रणभूमि में अरविंद केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ नरेन्द्र मोदी का खुद चेहरा बनना। वहीं रही-सही कसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा केजरीवाल सरकार के शराब घोटाला व भ्रष्टाचार आदि के मुद्दों को उठाने ने पूरी कर दी थी।

अवकाश शर्मा

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के परिणाम 8 फरवरी यानी कि शनिवार को आ चुके हैं, जिसमें भाजपा ने 27 वर्ष के बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। चुनावी रणभूमि में भाजपा को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार बिना कोई सीट हासिल किये शुन्य की हैट्रिक लगाने में सफल रही है। भाजपा गठबंधन को आम आदमी पार्टी से 3.6 फीसदी ज्यादा मत मिले हैं, जिसके चलते वह आप से 26 सीटें ज्यादा जीतने में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा दिये गये जीत के मंत्र के दम पर ही दिल्ली चुनाव में भाजपा ने वर्ष 2020 के मुकाबले लगभग 9 फीसदी वोट ज्यादा हासिल किया है। वहीं आम आदमी पार्टी को लगभग 10 फीसदी वोटों का नुकसान हुआ है और कांग्रेस का भी 2 फीसदी वोट बढ़ गया है। वर्ष 2020 से तुलना करें तो चुनावी रणभूमि में भाजपा की 71 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ीं हैं, भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़कर 48 सीटें जीतीं। वहीं आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31 फीसदी रहा, उसको 40 सीटों का नुकसान हुआ है।

वैसे देखा जाए तो वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव दर चुनाव गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों में भाजपा की पताका को लहराने का कार्य बखूबी किया है, लेकिन भाजपा देश के दिल दिल्ली को जीतने में बार-बार प्रयास के बावजूद भी विफल हो रही थी, लाख प्रयास के बावजूद भी दिल्ली की चुनावी रणभूमि में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल की कोई ठोस काट धरातल पर नहीं ढूंढ पा रहा था। वर्ष 2014 से ही केंद्र की सत्ता पर काबिज होने बावजूद भी दिल्ली की जनता बार-बार भाजपा को नकारने का कार्य कर रही थी, जो स्थिति भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत ज्यादा असहज करने वाली थी। चुनाव दर चुनाव भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा था। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए लगातार आत्ममंथन कर रहा था कि आखिरकार बार-बार कसर कहां पर रह जाती है, किसी कारण से दिल्ली का मतदाता लोकसभा चुनावों में भाजपा को गले लगा लेता है लेकिन वह विधानसभा चुनावों में दुत्कार देता है। दिल्ली के मसले पर देश के राजनीतिक गलियारों में भी केजरीवाल की सफलता का उदाहरण दिया जाने लगा था कि किस तरह से बहुत ही कम समय में वह दिल्ली के मतदाताओं के दिलों पर छा गए थे और फिर वर्ष 2013, वर्ष 2015 और 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने का कार्य किया था। लेकिन इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 'मोदी मंत्र' ने स्थिति को बदलने का कार्य कर दिया है। मतदाताओं ने दिल

खोलकर के भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने का कार्य किया कर दिया है, मोदी के चहरे के दम पर ही दिल्ली विधानसभा चुनावों में 48 सीट जीतकर के 27 वर्षों के बाद सत्ता पर काबिज होने का भाजपा को अवसर मिला है।

हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि भारतीय राजनीति में जब अरविंद केजरीवाल का पदार्पण हुआ था तो उस वक्त केजरीवाल ने दिल्ली व देश की जनता को संदेश दिया था कि वह ईमानदारी के साथ देश के विकास के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित हुए स्वच्छ गांधीवादी राजनीति करेंगे। उस वक्त केजरीवाल ने लोगों को बहुत-बहुत बड़े सपने दिखाए थे, राजनीतिक जीवन के लिए उच्च श्रेणी के मानदंड रखने का कार्य किया था, लेकिन जैसे ही वर्ष 2013 में केजरीवाल के हाथ दिल्ली की सत्ता आयी वह राजनीति में शुचिता लाने की बाद एक-एक करके भूलने लग गये थे। केजरीवाल ने गाडी, बंगाल और सुरक्षा पर बनाये गये अपने ही सिद्धांतों को सबसे पहले तिलांजलि देने का कार्य किया था, फिर केजरीवाल ने धीरे-धीरे दिल्लीवासियों को फ्री सुविधा देने का लालच देना शुरू किया और लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनकर के दिल्ली की सत्ता का जमकर के आनंद लिया। लेकिन इस बार वह अपने द्वारा बनाए सिद्धांतों के इसी चक्रव्यूह में बुरी तरह से फँस गए थे, क्योंकि राजनीति के लिए केजरीवाल के खुद के द्वारा तय किए गए सभी मापदंड उनके ही हाथों पूरी तरह से ध्वस्त कर दिये गये थे। दिल्ली के मतदाताओं को केजरीवाल की कथनी व करनी में स्पष्ट अंतर नजर आने लग गया था। दिल्ली के वासियों ने करीब से देखा कि ईमानदारी, सुचिता व जमीन पर रहकर के आम आदमी से जुड़े रहने की राजनीति के सिद्धांतों पर केजरीवाल एंड कंपनी केवल फाइलों के भीतर ही अमल कर रही है, केजरीवाल का एक-एक करके साथ छोड़ते पुराने साथी पार्टी के भीतर लोकतंत्र के हाल पर जनता के बीच जाकर के गवाही दे रहे हैं, जिसका पूरा लाभ टीम मोदी ने इस बार के विधानसभा चुनावों में लिया और केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने का काम कर दिया।

जिस तरह से देश के दिल राजधानी दिल्ली की चुनावी रणभूमि में नरेन्द्र मोदी सेना ने जबरदस्त ढंग से हमलावर होकर के केजरीवाल की सेना को करारी हार देकर के प्रचंड विजय हासिल की है, वह आगामी कई दशकों तक देश की चुनावी राजनीति में एक नजीर बन गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हमलों के आगे टीम अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली की चुनावी रणभूमि में लड़ना इस बार बेहद ही कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के मतदाताओं के लिए फ्री बांटों की रणनीति की काट ढूंढना देश के भोले-भाले आम जनमानस को असंभव लगता था, क्योंकि केजरीवाल ना सिर्फ चुनावी रणभूमि में मतदाताओं से तरह-तरह के लोकलुभावन वादे ही कर रहे थे, बल्कि वह पहले से ही बहुत सारी फ्री की रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं पर धरातल पर अमल भी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दिल्ली में भाजपा को पुनर्जीवित करना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि देश की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को केजरीवाल के पक्ष में रहने वाले मतदाताओं को तोड़कर के भाजपा के पक्ष में लाना असंभव कार्य लगता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जादुई व्यक्तित्व व ओजस्वी विचारों ने उस कार्य को कर दिखाया, मोदी ने दिल्ली की चुनावी रणभूमि में आम आदमी पार्टी को हराते हुए भाजपा को पुनर्जीवित करने के लिए जीवन देनी वाली कारगर संजीवनी बूटी बनने का कार्य बखूबी कर दिया। दिल्ली की चुनावी रणभूमि में अरविंद केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ नरेन्द्र मोदी का खुद चेहरा बनना। वहीं रही-सही कसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा केजरीवाल सरकार के शराब घोटाला व भ्रष्टाचार आदि के मुद्दों को उठाने ने पूरी कर दी थी। मोदी ने दिल्ली की जनता को समझाया कि आप सरकार दिल्ली के वासियों के लिए आप' दा बन चुकी है, भ्रष्टाचार के मामलों के चलते केजरीवाल कुल 177 दिन तक जेल में बंद रहे थे, जिसके चलते ही मोदी ने केजरीवाल को बार-बार 'कट्टर बेईमान' कहा था। कभी बंगला, गाड़ी व सुरक्षा ना लेने की कसम लेने वाले केजरीवाल के सरकारी बंगले 'शीशमहल' पर 45 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि खर्च करके मोदी को एक और चुनावी मुद्दा स्वयं ही दे दिया था, जिसको मोदी व उनकी टीम ने बड़ा मुद्दा बनाया और चुनाव के पहले इसे 'शीशमहल' कहकर इसको आम जनमानस के बीच जमकर के प्रचारित करने का कार्य बखूबी करके केजरीवाल की छवि को जनता की अदालत में बट्टा लगाने का कार्य सफलतापूर्वक कर दिया था, मोदी ने पूरे चुनाव इस मुद्दे को लेकर के केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल की फ्री बांटों की काट ढूंढते हुए दिल्ली में मतदान से 3 दिन पहले केंद्रीय बजट में 12 लाख तक के इनकम टैक्स को फ्री करने का बड़ा दांव चल कर केजरीवाल की थोक में वोट काटने का काम कर दिया था, क्योंकि दिल्ली में 67 फीसदी आबादी मध्यमवर्गीय है, जोकि आम आदमी पार्टी को एकतरफा वोट देने का कार्य कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने हर कार्यक्रम में दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया कि हम मौजूदा आप सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे और महिलाओं व बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए देने का कार्य करेंगे। जिन्होंने दिल्ली के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने का कार्य किया और भाजपा को चुनावी रणभूमि में जीता दिया।

हालांकि देश के बहुत सारे लोगों व राजनीतिक विश्लेषकों यह लगता था कि केजरीवाल के आगे 27 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में कमल खिलाना इस बार भी असंभव है। लेकिन मोदी मंत्र के दम पर भाजपा इस असंभव को भी संभव बनाने में अब सफल हो गयी है। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चहरे पर दिल्ली का पूरा चुनाव लड़ा और नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें दिल्ली में एक ऐसी सरकार मिलेगी जो दिल्ली के निवासियों की सेवा करेगी, जो विकसित भारत 2047 के सपने को प्राप्त करने में बढ़-चढ़कर के अपना योगदान देगी, जो दिल्ली वासियों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी सेवा करेगी, जो दिल्ली के विकास का शानदार रोड़मैप बनाकर के धरातल पर कार्य करेगी।

कपिल चौहान

आखिर दिल्ली में क्यों ढ़हा 'आप' का किला?

दिल्ली में आप सरकार ने करीब एक दशक तक शासन किया और लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जनता के बीच असंतोष और बदलाव की इच्छा बढ़ी थी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी और वादों को पूरा न करने के आरोपों ने सत्ता विरोधी लहर को मजबूत किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं ने विकल्प के रूप में भाजपा की ओर रुख किया।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला बुरी तरह ढ़ह गया है। आतिशी को छोड़कर पार्टी के लगभग तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए और आप ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी लेकिन 2020 में यह संख्या घटकर 62 रह गई थी। वहीं, भाजपा ने 2015 में मात्र 3 सीटें जीती थी जबकि 2020 में 8 सीटें जीतने में सफल हुई थी और बंपर जीत के साथ पूरे 27 सालों बाद अब दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हुई है। 27 साल पहले भाजपा की सुषमा स्वराज आखिरी बार कुल 52 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी और अब 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में बड़ी वापसी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे और यह विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के लिए नाक का बहुत बड़ा सवाल था लेकिन भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे और क्यों पार्टी की राजनीतिक स्थिति इतनी कमजोर हुई?

दिल्ली में आप सरकार ने करीब एक दशक तक शासन किया और लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जनता के बीच असंतोष और बदलाव की इच्छा बढ़ी थी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी और वादों को पूरा न करने के आरोपों ने सत्ता विरोधी लहर को मजबूत किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं ने विकल्प के रूप में भाजपा की ओर रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने, दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसा बनाने

और साफ पानी उपलब्ध कराने जैसे जो तीन प्रमुख वादे दिल्ली की जनता से किए थे, वे एक दशक में भी पूरे नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह इत्यादि पार्टी के शीर्ष नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाते हुए 'आप' की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को कमजोर किया। इन घटनाओं ने पार्टी की स्वच्छ राजनीति के दावे पर सवाल खड़े किए और जनता के विश्वास को कमजोर किया। खासतौर से केजरीवाल की गिरफ्तारी और बाद में उनके इस्तीफे के कारण पार्टी के नेतृत्व में अस्थिरता आई और केजरीवाल की विश्वसनीयता में बड़ी कमी आई। केजरीवाल ने हमेशा से वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए थे लेकिन शीशमहल के मुद्दे पर वे स्वयं ह्यवीआईपी कल्चरह्ल के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गए थे, भाजपा-कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आप को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने कहा था कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, गाड़ी, बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था लेकिन सत्ता मिलने के बाद उन्होंने लग्जरी गाड़ियां तो ली ही, केंद्र से जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की शीर्ष सुरक्षा भी ली।

पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व के मुद्दों ने भी आप की हार में बड़ा योगदान दिया। कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने या निष्क्रिय होने से संगठनात्मक ढ़ांचे में कमजोरी आई। इसके अलावा नेतृत्व के प्रति असंतोष और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी ने कार्यकताओं और समर्थकों के मनोबल को प्रभावित किया। आप सरकार ने बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में मुफ्त सेवाओं की घोषणा की थी लेकिन विपक्ष ने इसे ह्यरेवड़ी संस्कृतिह्ल कहकर आलोचना करते हुए इसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया। इसके अलावा, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में आई समस्याओं ने जनता के बीच नकारात्मक धारणा बनाई, जिससे ह्यआपह्ल की लोकप्रियता में गिरावट आई। दिल्ली में सड़क, परिवहन और स्वच्छता के क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढ़ांचे के विकास में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। इसके अलावा प्रदूषण, जलभराव और कूड़े के ढ़ेर जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होने से जनता में केजरीवाल सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी थी। इन मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता ने मतदाताओं को निराश किया। दिल्ली में आप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण मुफ्त बिजली-पानी जैसी योजनाओं को माना जाता रहा लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा ने भी 'आप' वाला ही दांव खेला और अपने चुनावी संकल्पों में महिलाओं, बच्चों व युवाओं से लेकर ऑटो रिक्शा चालकों तक के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो की ही, साथ ही यह ऐलान भी किया कि वह सत्ता मिलने पर आप द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को जारी करेगी। भाजपा की इन घोषणाओं से आप की चुनौती बहुत बढ़ गई थी।

विपक्ष और खासकर भाजपा की मजबूत रणनीति तथा भाजपा का मुखर प्रचार आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। भाजपा ने आप सरकार की तमाम कमजोरियों को उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भी इस तरह टिकट बांटे,

अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने, दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसा बनाने और साफ पानी उपलब्ध कराने जैसे जो तीन प्रमुख वादे दिल्ली की जनता से किए थे, वे एक दशक में भी पूरे नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह इत्यादि पार्टी के शीर्ष नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

जिसने कई सीटों पर आप को आसान जीत से रोकने में अहम भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार, विकास की कमी और अन्य मुद्दों पर केंद्रित अभियानों ने जनता के बीच आप के प्रति नकारात्मक धारणा बनाई। भाजपा ने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया, जिससे आप के समर्थन में बड़ी कमी आई। चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चचाएं थी लेकिन हरियाणा विधानसभा में दोनों के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण दिल्ली में भी दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके चलते विपक्षी मतों का विभाजन हुआ और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने के फैसले ने आप की रणनीतिक कमजोरी को उजागर किया और विपक्षी एकता की कमी का स्पष्ट संकेत दिया। इसका भी दिल्ली के मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पिछले दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2015 में कांग्रेस को 9.7 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन 2020 में मतों का प्रतिशत गिरकर महज 4.3 फीसद रह गया था लेकिन इस बार कांग्रेस के मत प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका नुकसान भी आप को भुगतना पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में 'आप' को ऐसी 'आपदा' करार देते हुए भाजपा कार्यकताओं में जोश भरने का भरपूर प्रयास किया, जिसने जनता के फायदे के लिए मिलने वाली केंद्र की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, उससे मतदाताओं के बीच आप की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा और प्रधानमंत्री के 'आपदा' वाले नारे से भाजपा कार्यकताओं का जोश कई गुना बढ़ा। दिल्ली की आबादी में पूर्वांचल (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड) से आए लोगों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और विपक्ष ने इस समुदाय की समस्याओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए आप सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग की समस्या, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देना, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों ने पूर्वांचली समुदाय में असंतोष बढ़ाया। इस उपेक्षा के कारण इस समुदाय का समर्थन आप से हटकर अन्य दलों की ओर गया और इसका नुकसान आप को भुगतना पड़ा।

बहरहाल, केजरीवाल का दावा था कि वे राजनीति में नैतिकता और शुचिता की राजनीति करने आए हैं लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों के चुनावों में जिस तरह से पैसा खर्च किया और दिल्ली में कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपये खर्च कर जो 'शीशमहल' बनवाया, उसे लेकर उन पर लगातार लगते रहे आरोपों का पार्टी के पास ही कोई कारगर जवाब नहीं था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े-बड़े दावों के बीच शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के छींटे, केजरीवाल की तानाशाहीपूर्ण नेतृत्व शैली, उनका अड़ियल रवैया, इस तरह की बातों से मतदाताओं का केजरीवाल से मोहभंग होता गया और भाजपा एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरती गई। कुल मिलाकर, केजरीवाल की कथनी और करनी के बीच बड़ा अंतर आप की हार का बड़ा कारण रहा। दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों और बारिश के मौसम में जलभराव के मुद्दे ने भी दिल्ली में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इस मुद्दे पर आप को घेरा, जिसने आप की लुटिया डुबोने में बड़ी भूमिका निभाई।

भूलोक का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ

सनातन संस्कृति में कुम्भों का विशद वर्णन है। ज्योतिष की दृष्टि से ब्रह्मांड में 12 कुंभ होते हैं। जिनमें से 8 देवलोक में और 4 भूलोक में होते हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, जो नक्षत्रों और ग्रहों की युति और दृष्टि संबंध से निरंतर है। देवलोक में संपन्न होने वाले कुंभों में ३३३ कोटि देव उसके अनुष्ठान के लाभ लेते हैं, लेकिन शेष 4 कुंभ भारत भूमि पर ही चार पवित्र स्थानों पर संपन्न होते हैं।

ऋग्वेद में एक ऋचा है -

उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां धियो विप्रो अजायत।।

अर्थात संसार को उचित निर्देशन देने वाले विप्र- ब्रह्मविद्या के ज्ञान से परिपूर्ण देवतुल्य ऋषि मुनि, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर ध्यान साधना और अभ्यर्चन से सम्पन्न होते हैं....!

वे ऋषि मुनि सदैव ध्यानस्थ होकर उस परमात्मा

ललित कुमार

को प्राप्त होते हैं...जिनके श्वास प्रश्वास से लोक कल्याण होता है। इसलिए मोक्षार्थी पर्वतों की गुफाओं और नदियों के संगम पर बैठ कर परमात्मा का ध्यान करते हैं तथा सर्वत्र व्याप्त अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। आत्मा वस्त्र की भांति शरीर को बदलकर नए शरीर को प्राप्त होती रहती है। जाती है और पुनः पुनः नई यात्रा आरम्भ होती रहती है। यह जीवन क्षण क्षण में नवता को उपलब्ध होता है, तभी रमणीय होता है। राम को प्राप्त होना तो अत्यंत कठिन है, लेकिन राम का दर्शनलाभ तो लिया जा सकता है...जैसे जैसे विचारों का तमस हटता है...मनुष्य रजस को प्राप्त होता है...और मार्ग प्रकाशित होना आरम्भ हो जाता है...जैसे जैसे रजस से आगे बढ़ने का मार्ग बनता है तो उस परम पिता परमात्मा में लीन होने की अवस्था आ जाती है...यही सतोगुण का प्रभाव अपना आवरण प्रसारित कर देता है और तमसो मा सद्गमय की अवस्था जन्म लेती है...लेकिन ये सब कह देना सहज और सरल है...यह बहुत कठिनाइयों से भरा मार्ग है...आध्यात्मिक कठिनाइयों पर ज्ञानचर्चा और पुण्य प्राप्त करने के लिए सनातन के पुत्र कुंभ पर्व पर पुण्योदय करते हैं। सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा की विशेष अवस्था की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुंभ स्नान के माध्यम से अभी तक के ज्ञात कुंभ/अर्धकुंभ में अधिकतम २४ करोड़ सनातनपुत्रों के स्नान का वर्णन मिलता है। लेकिन २०२५ का महाकुंभ ब्रह्माण्ड के कुंभ से भी अधिक स्नानार्थियों की संख्या को पार कर गया है। देवलोक के आठ कुंभ केवल देवताओं के लिए होते हैं, लेकिन संख्याक्रम वहां ३३ कोटि है....और पृथ्वी पर केवल

भारत भूमि पर कुंभ का आयोजन होता है। २०११ की जनगणना के अनुरूप अनुमान के अनुसार भारत में प्रायः ११० कोटि सनातनी रहते हैं। जिनमें ० से ६ वर्ष वय के प्रायः २५ प्रतिशत, ७ से १४ वर्ष के वयवर्ग में प्रायः २२ प्रतिशत, १५ से ५९ वयवर्ष के प्रायः ५२ प्रतिशत और ६० एवं उससे अधिक आयुवर्ग के प्रायः एक प्रतिशत सनातनी हैं।

इस आलेख के लिखे जाने तक प्रायः ६० कोटि से अधिक सनातन के पुत्र प्रयागराज के इस पवित्र महाकुंभ में अमृत से परिपूर्ण त्रिवेणी की धारा में संगम पर स्नान का पुण्य अर्जित कर चुके हैं। यदि भारत की जनसंख्या के आंकड़े पर दृष्टि डालें तो कह सकते हैं कि समस्त हिन्दू सनातन के पुनर्जागरण का साक्षी हो चुका है और वह उमंग में है, उत्साह में है और दैवीय कृपा से तरंगित होकर अपने इष्ट की शरण में है। गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का यह कालखंड सनातन का स्वर्ण काल है। जागृत हिन्दू अपने तीर्थों पर अपने इष्ट से प्रार्थनारत है। अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहा है। अयोध्या, मथुरा - काशी से लेकर पूरे देश के सभी तीर्थ इस पावन प्रवाह में प्रवाहित होकर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। यह अद्भुत आध्यात्मिक अवसर है, जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता है। पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सन्त एवं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और समस्त मंत्रिमंडल, उच्च अधिकारी, देश विदेश से पधारे श्रद्धालु भक्त और विश्व के अनेक राष्ट्रप्रमुख महाकुंभ स्नान करके अपने पुण्योदय कर रहे हैं। ७० से अधिक देशों के श्रद्धालुओं ने भी इस बार महाकुंभ में स्नान पुण्य का लाभ उठाया है।

इस कुंभ में अंतिम अमृत स्नान के लिए निर्धारित २६ फरवरी तक प्रायः ७० कोटि (करोड़) सनातनी स्नान कर चुकेंगे ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार सनातन के सभी परिवार किसी न किसी प्रकार से इस महाकुंभ में स्नान करके पुण्यार्जन कर चुके हैं। क्योंकि इस महाकुंभ में देवलोक के कुंभ से भी द्विगुणित अधिक संख्या में स्नान संतति ने पवित्र स्नान किया है। जोकि एक ऐतिहासिक सर्वोच्च प्रमाण है। ऐसा महाकुंभ अभी तक ब्रह्मांड में नहीं हुआ है। इसलिए इस कुंभ को महाकुंभ कहा गया है। इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य, अलौकिक एवं ऐतिहासिक बनाने में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस लोक कल्याण के कार्य के लिये इतिहास सदैव स्मरण रखेगा। उनकी महान सेवाओं के लिए सारा सनातन जगत उनका सदैव आभारी और ऋणी रहेगा।

कुंभ में साधुओं के अखाड़ों का गजब इतिहास

प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत पहुंचे हुए हैं। अलग-अलग अखाड़ों के साधु-संतों का जमावड़ा देखने दुनिया भर से लोग संगम किनारे जुट रहे हैं। इन साधुओं में एक से एक तपस्वी संत देखने को मिल रह हैं। सही मायनों में कुम्भ मेले की सबसे अधिक शोभा साधु-संतों के अखाड़ों से ही होती है। उनके दर्शन लाभ के लिये हर कोई उत्सुक दिखता है।

आमतौर पर अखाड़ा उस स्थान को कहते हैं, जहां पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन साधु-संतों के समूह वाले अखाड़ों का अर्थ अलग होता है। साधु-संतों के समूह को अखाड़ा नाम आदि शंकराचार्य ने दिया था। साधु-संतों के अखाड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षक के प्रतीक माने जाते हैं। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के संन्यासियों के मान्यताप्राप्त मुख्य रूप से कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें शैव संन्यासी संप्रदाय के 7, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा किन्नर साधुओं का भी है, जिसे कुछ वर्ष पहले ही धर्मसंसद ने मान्यता दी है। साधु-संतों के अखाड़ों का इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता है कि प्राचीन समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने शस्त्रविद्या में निपुण साधुओं के संगठन तैयार किए थे, जिन्हें अखाड़ा नाम दिया गया। महाकुंभ में अखाड़ों की उपस्थिति सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अखाड़े पवित्र अनुष्ठानों, ग्रंथों और परंपराओं को संरक्षित कर इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। वहीं नागा साधुओं के अखाड़े युद्ध से जुड़ी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, ताकि पवित्र स्थलों की रक्षा हो सके।

इस वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ या महाकुंभ के दौरान विशेष तिथियां गंगास्नान के लिए शुभ मानी जाती हैं। इन शुभ तिथियों पर साधु-संत सबसे पहले स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। सबसे पहले शाही स्नान करने का अधिकार नागा साधुओं के अखाड़ों को दिया गया है। इसलिये कि ये अखाड़े सनातन धर्म की पताका ऊंची रखने और धर्म की सुरक्षा करने के लिये हमेशा आगे रहते हैं।

नागा साधु शस्त्रधारी होते हैं, लिहाजा उनके स्नान के समय किसी भी दूसरे व्यक्ति या अखाड़े के साधु का स्नान करना वर्जित होता है। नागा साधुओं के स्नान के समय सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

समुद्र मंथन से मिले थे 14 रत्न

सनातन धर्म से संबंधित सभी लोग समुद्र मंथन की कथा को जानते हैं। यह कथा समुद्र से निकले अमृत कलश से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण कर देवताओं को अमृतपान करवाया था। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा 13 अन्य वस्तुएं भी प्रकट हुई थी। धर्मग्रंथों के अनुसार, एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन (ऐश्वर्य, धन, वैभवरहित) हो गया था और इन्द्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी कहा कि इस मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमरत्व प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वासुकि नाग की नेती बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया। इस मंथन से एक-एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले।

हलाहल (विष) : समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। इस विष की ज्वाला से देवता और दैत्य जलने लगे। इस पर सबने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए। किन्तु देवी पार्वती ने विष को उनके कण्ठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से शिव का कण्ठ नीला पड़ गया। इसीलिये महादेव को नीलकण्ठ भी कहा जाता है। हलाहल को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे साँप, बिच्छू आदि विषैले जन्तुओं ने ग्रहण कर लिया और वे विषैले बन गए।

कामधेनु गाय : हलाहल विष के बाद मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र (यज्ञ) की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है, जिसमें दैवीय शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगो के दुःख व पीड़ा दूर हो जाती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था।

उच्चैश्रवा घोड़ा : समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्मग्रंथों के अनुसार इसे देवराज इन्द्र को दे दिया गया था। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे- जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों। इस घोड़े का रंग श्वेत था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है।

ऐरावत हाथी : समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इन्द्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत इन्द्र को दे दिया गया। रत्नों के बंटवारे के समय इन्द्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था।

कौस्तुभ मणि : समुद्र मंथन के दौरान पांचवे नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर ली। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहां भी यह मणि होती है, वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती है।

कल्पवृक्ष : समुद्र मंथन में छठे नंबर पर कल्पवृक्ष प्रकट हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया।

रंभा नामक अप्सरा : समुद्र मंथन में 'रंभा' नामक अप्सरा भी प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थीं और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वंय ही देवताओं के पास चलीं गई। बाद में देवताओं ने रंभा अपने राजा इन्द्र को सौंप दी,

जो उनकी सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई।

देवी लक्ष्मी : समुद्र मंथन के दौरान आठवें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। क्षीरसमुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्रीअंगों से दिव्य कान्ति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि वे उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया।

वारुणी (मदिरा) : समुद्र मंथन के दौरान नौवें नंबर पर वारु णी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे।

चन्द्रमा : समुद्र मंथन के दौरान दसवें नंबर पर चन्द्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया।

पारिजात वृक्ष : समुद्र मंथन से ग्यारहवें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया।

पांचजन्य शंख: समुद्र मंथन पांचजन्य शंख प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री हैं और शंख उनका सहोदर भाई है। यह भी मान्यता है कि जहां शंख है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है।

भगवान धन्वन्तरि : समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिये श्याम वर्ण, चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वन्तरि भी प्रकट हुए। देवराज इन्द्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वन्तरि ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यन्त पीड़ित हो गए तो इन्द्र ने भगवान धन्वन्तरि जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लें। इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वन्तरि ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। धन्वन्तरि-संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रन्थ है।

अमृत : समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला चौदहवां और अंतिम रत्न 'अमृत' था। धर्मग्रंथों में यह अमरत्व प्रदान करने वाले रसायन है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहां यह सोम के विभिन्न पयार्यों में से एक है। अमृत को देखकर देवता और दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। इस तरह देवता अमर हो गए और सनातन धर्म चिरायु हो गया।

देखने लायक होती है अखाड़ों की पेशवाई

महाकुंभ के मेले में देश-विदेश से लाखों-करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक उत्सव के दौरान संगम समेत प्रमुख घाटों पर स्नान के लिए साधु संतों का जमावड़ा लगता है। इस दौरान उनके अखाड़ों की पेशवाई होती है, जिसे बहुत खास माना जाता है।

कुंभ और महाकुंभ से बड़ा धार्मिक उत्सव दुनिया में कोई नहीं होता। महाकुंभ सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजकर रखने और धर्म का समाज से रिश्ता बनाए रखने का महापर्व माना जाता है। साधु-संतों को महाकुंभ का वाहक माना जाता है। इन साधु संतों ने विपरीत हालात में भी धर्म को संभालकर रखा और मजबूत किया। इतिहास गवाह है कि इसके लिये साधु-संत न केवल धर्म, बल्कि राष्ट्र के लिये भी हथियार उठाने से पीछे नहीं रहे। जब-जब सनातन धर्म पर दूसरे मजहबों के शासकों ने कुचक्र चलाया, साधुओं के अखाड़ों ने उनसे युद्ध किया और अपना खून बहाकर धर्म की रक्षा की।

महाकुंभ क्षेत्र में जब साधु प्रवेश करते हैं तो पेशवाई के साथ आते हैं। पेशवाई के दौरान उनकी भव्य शोभायात्रा निकलती है, जिसे देखने लाखों लोग पहुंचते हैं। विजय यात्रा के रूप में साधु-संत पालकियों, घोड़ों, रथों और हाथियों पर बैठकर जब पेशवाई करते हैं तो देखते ही बनता है। इस दौरान साधुओं के एक हाथ में धर्मग्रंथ होते हैं तो दूसरे में हथियार। हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच ढोल-नगाड़ों के बीच वे हथियारों का प्रदर्शन, तलवारबाजी और युद्ध के करतब दिखाते हैं। अखाड़ों के प्रमुख संतों की राजा-महाराजों की तरह हाथी, घोड़ों और रथों पर शाही सवारी निकलती है।

पेशवाई के दौरान पूरे रास्ते में श्रद्धालु साधु-संतों का स्वागत करते हैं। इन साधु-संतों के हाथ में अपने-अपने अखाड़ों की ध्वजा होती है। ठीक उसी तरह, जैसे राजशाही के दौरान राजाओं-महाराजाओं की यात्रा ध्वजा के साथ हुआ करती थी। संत ध्वजा हाथ में लिए अपनी सेना के साथ पूरे रीति-रिवाज से निकलते हैं। कुंभनगरी में साधुओं की पेशवाई को देखने के लिए विश्वभर से लोग आते हैं। इस दौरान साधु-संतों का उत्साह आसमान छूता दिखाई देता है। श्रद्धालुओं के लिये यह दृश्य कभी न भूलने वाला होता है।

महाकुंभ में सबसे नया किन्नर अखाड़ा

किन्नर अखाड़ा किन्नरों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। यह अखाड़ा किन्नरों को अनुशासन में बांधने के लिये भी काम करता है। किन्नर साधु अपनी अनूठी पहचान के कारण ध्यान आकर्षित करते हैं।

गले में सोने के मोटे-मोटे हार, कलाई पर रुद्राक्ष, सोने और हीरे से बने ब्रेसलेट, कानों में कई तोले की ईयर-रिंग, नाक में कंटेंपरेरी नथ, माथे पर त्रिपुंड और लाल बिंदी। यह पहचान है किन्नर अखाड़े के मुखिया साधु आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ रथ-घोड़े, गाजे-बाजे के साथ पहले प्रयागराज नगर और फिर छावनी प्रवेश किया। एक हजार किन्नर साधुओं की अगुआई करने वाले इस अखाड़े में भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों से आए किन्नर साधु शामिल हैं। इनके आने का सिलसिला थमा नहीं है। हर रोज महाकुंभ में किन्नर साधु आकर्षक वेशभूषा के साथ पहुंच रहे हैं। ये साधु अपने मेकअप में बहुत समय लगाते हैं और कहते हैं कि वे अपने प्रभु के लिये श्रंगार करते हैं।

दरअसल, किन्नरों की अस्मिता के लिये

मनोज शर्मा

संघर्षरत डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कई वर्षों से काम कर रही थीं। धर्मग्रंथों की मर्मज्ञ और कई भाषाओं में बोलने वाली डॉ. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी बताती हैं कि उनके मन में किन्नर अखाड़ा बनाने का जब विचार आया तो उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित किया और साल 2015 में किन्नर अखाड़े की स्थापना की। जब यह बात अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। घोर विरोध के बाद भी 2016 में उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े ने अपना अलग कैंप लगाया।

इस दौरान विद्वान संतों से उनका शास्त्रार्थ हुआ और आखिर उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह मिल गई। लेकिन अखाड़ा परिषद ने उनके शाही स्नान करने पर आपत्ति की। इसके बाद किन्नर अखाड़े के संतों ने खुद को उपदेव बताते हुए शाही स्नान किया था। उज्जैन में किन्नर अखाड़ा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना और लोगों का भी इन्हें बहुत साथ मिला।

आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अनुसार, 2019 में इनकी मुलाकात जूना अखाड़े के संरक्षक हरि गिरि महाराज से हुई। तब जूना अखाड़े के साथ इनका अनुबंध हुआ। इस अनुबंध में यह तय किया गया कि अब कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। जूना अखाड़े की स्वीकृति के बाद अन्य अखाड़ों ने भी किन्नर अखाड़े के प्रति अपना विचार बदल लिया।

देश-विदेश से आए श्रद्धालु बोले: आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का अवसर है महाकुम्भ

- केवल देश ही नहीं, विदेशी श्रद्धालुओं व सैलानियों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है महाकुम्भ 2025 का खुमार
- महाकुम्भ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर श्रद्धालु हुए धन्य, कहा: जीवन हुआ सफल, बर्ड फेस्टिवल ने बढ़ाया विदेशी सैलानियों का आकर्षण

महाकुम्भ-2025 के अंतर्गत पूरी दुनिया से स्नानार्थियों व सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं और सैलानियों ने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ ही महाकुम्भ मेला क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का आवलोकन किया। वहीं, कई विदेशी सैलानी महाकुम्भ के अंतर्गत आयोजित हो रहे बर्ड फेस्टिवल का हिस्सा बनकर जीव-जंतुओं व पक्षियों के संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की भी जानकारी लेते दिखे। उनके अनुसार, महाकुम्भ केवल मनुष्य ही नहीं, पक्षियों व जीव-जंतुओं के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त कर रहा एक महाआयोजन है जिसका हिस्सा बनकर वह खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।

मानवता व धर्म के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है महाकुम्भ

दिल्ली से त्रिवेणी संगम में स्नान करने आईं मोनिका ने बताया कि यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। उन्होंने कहा कि इतने लोगों को एका साथ आस्था की डोर में बंधकर त्रिवेणी संगम में स्नान करते देखना अविस्मरणीय क्षण था। मैंने मीडिया में तो इन चीजों को देखा था मगर यहां आकर स्वयं महाकुम्भ के इन खूबसूरत क्षणों को जीना एक ऐसा अनुभव है जिसने धर्म और मानवता के प्रति मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया है। यह एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा थी।

वहीं दिल्ली से ही आईं शीघ्र बंसल ने कहा कि मैं पहली बार कुम्भ के आयोजन में प्रयागराज आई हूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरिएंस था। मैं ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं इसके बावजूद यहां की दिव्य आध्यात्मिक व सकारात्मक ऊजाओं को अनुभूत कर सकी। यहां पर जिस प्रकार सकुशल जनप्रबंधन हो रहा है इसके लिए स्थानीय प्रशासन बधाई का पात्र है।

सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है महाकुम्भ में जुटी अपार भीड़

एक अन्य स्नानार्थी सुमिता वाही ने बताया कि मैं आध्यात्मिक अभिरुचि रखती हूं इसलिए मेरे लिए यह एक बेहद विशिष्ट क्षण है। उन्होंने कहा कि यहां इतनी अपार भीड़ जुटी हुई है मगर सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। यही कारण है कि महाकुम्भ मेला क्षेत्र में आपको अपार सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है।

मनुष्यों के साथ ही पक्षियों व जीव-जंतुओं के संरक्षण का भी माध्यम बना महाकुम्भ

यूके से आईं एमा ने बताया कि मैं पहली बार कुम्भ मेला में भाग लेने भारत आई हूं। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ में दिव्यता को अनुभूत करने के साथ यहां आयोजित हुए बर्ड फेस्टिवल को भी देखने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के साथ ही पर्यावरण और जैविक संरक्षण की दिशा में हो रहे कार्यों की जितनी प्रशंसा हो वह कम है। एक अन्य विदेशी सैलानी ने भी बर्ड फेस्टिवल में भारत के कंसर्वेशन एक्सपर्ट्स से हुए इंटरैक्शन को यादगार बताते हुए प्रयागराज की धरती की जमकर तारीफ की और उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई कि महाकुम्भ मनुष्यों के साथ ही पक्षियों व जीव-जंतुओं के संरक्षण का भी माध्यम बन रहा है।

हर व्यवस्था पर सीएम योगी ने रखी पैनी नजर

अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 16 बार किया प्रयागराज का दौरा

इंद्रेश शर्मा

महाकुम्भ 2025 धीरे-धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुम्भ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक भव्यता का जीवंत प्रमाण है। सीएम योगी के नेतृत्व में यह महाकुम्भ श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है।

टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधाओं के अद्भुत समन्वय से यह महाकुम्भ विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहा है। इसको अविस्मरणीय बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी विशेष योगदान रहा है। वह महाकुम्भ की धड़कन बन पल पल पूरे आयोजन को लीड करते नजर आए। 06 अक्टूबर 2024 को महाकुम्भ का लोगो, वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद से अब तक वह 16 बार प्रयागराज पहुंचे, हर व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और तैयारियों को समय से पहले पूरा करने का संकल्प दोहराया। महाकुम्भ की शुरूआत के बाद सीएम और सजग नजर आए और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर उतरकर हर व्यवस्था, सुविधा को सुनिश्चित किया।

परखीं तैयारियां, संतों का किया सत्कार

अपने प्रयागराज दौरों पर सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों, व्यवस्थाओं और सुविधाओं की समीक्षा की, बल्कि 13 अखाड़ों, प्रमुख संतों और धर्मगुरुओं से संवाद कर महाकुम्भ को और भव्य बनाने के सुझाव लिए। श्रद्धालुओं की सुविधाओं से लेकर साधु-संतों के सत्कार तक, हर व्यवस्था का सीएम योगी ने खुद जायजा लिया। यही नहीं, अमृत स्नान और प्रमुख स्नान पर्वों पर सीएम योगी ने सरकारी आवास से रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतरीन बनी रहे। अपनी सतत निगरानी से उन्होंने महाकुम्भ 2025 को संस्कृति, आध्यात्म और आधुनिकता का संगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

06 अक्तूबर को महाकुम्भ का लोगो, वेबसाइट और मोबाइल एप का लोकार्पण करने के बाद से मुख्यमंत्री योगी अब तक कुल 16 बार प्रयागराज आए। वहीं, महाकुम्भ की शुरूआत से लेकर अब तक उन्होंने कुल 8 बार यहां का भ्रमण किया। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा के साथ ही उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन भी किया। साधु संतों के साथ संवाद स्थापित कर महाकुम्भ को भव्य बनाने के लिए सुझाव भी लिए तो हर वर्ग और संप्रदाय के संतों का सत्कार कर दिल भी जीता। ग्राउंड जीरो के साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भी कई बार महाकुम्भ को लेकर बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए उन्होंने ग्राउंड रियलिटी भी जानी।

महाकुम्भ आयोजन को लेकर सीएम योगी की गतिविधियों की झलक

- **27 नवंबर :** इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। महाकुम्भ से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
- **07 दिसंबर :** प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पूर्व संत समाज को आमंत्रित किया। अरैल बंधा रोड, त्रिवेणी पुष्प, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट और शिवाजी पार्क का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और अस्थाई पुलिस लाइन का उद्घाटन भी किया।
- **12 दिसंबर :** पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय अस्पताल, किला घाट जेटी, पीएम कार्यक्रम स्थल, अक्षय वट, हनुमान कॉरिडोर, सरस्वती कूप का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया।
- **13 दिसंबर :** पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में सहभागिता।
- **23 दिसंबर :** टेंट सिटी का निरीक्षण, दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती, स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड का निरीक्षण और तैयारियों की समीक्षा।
- **31 दिसंबर :** बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण, संगम नोज का निरीक्षण, त्रिवेणी पूजन, समीक्षा बैठक।
- **09 जनवरी :** 13 अखाड़ों, दंडीबाड़ा, खाकचौक और योगी महासभा के शिविर में पहुंचे, डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन, प्रेस कान्फ्रेंस, डिजिटल महाकुम्भ एक्सपीरिएंस सेंटर का उद्घाटन, तैयारियों की समीक्षा।
- **10 जनवरी :** प्रसार भारती के चैनल कुम्भवाणी का शुभारंभ, परिवहन निगम की बसों को दिखाई हरी झंडी।
- **19 जनवरी :** पूज्य शंकराचार्य, संत महात्माओं से मुलाकात, ओडीओपी प्रदर्शनी, पुलिस गैलरी, संविधान गैलरी, पर्यटन गैलरी, एनसीजेडसीसी पवेलियन का शुभारंभ। स्वामी चिदानंद के शिविर में मोरारी बापू की कथा का श्रवण।
- **22 जनवरी :** महाकुम्भ में कैबिनेट बैठक, पूरे मंत्री परिषद के साथ पावन संगम स्नान।
- **25 जनवरी :** अखिल भारतवर्षीय अवधूतभेष बारह पंथ योगी महासभा के कार्यक्रम में, गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा में, विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में सहभागिता। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य से भेंट।
- **27 जनवरी :** गृहमंत्री अमित शाह के महाकुम्भ आगमन पर स्वागत और त्रिवेणी संगम में पूजन।
- **01 फरवरी :** संगम नोज का स्थलीय निरीक्षण, सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में सहभागिता, भारत सेवाश्रम शिविर का दौरा। उपराष्ट्रपति का स्वागत और दुनिया के 73 देशों के राजनयिकों से किया संवाद व समीक्षा बैठक।
- **04 फरवरी :** बौद्ध महाकुम्भ कार्यक्रम में सहभागिता, मीडिया से संवाद, भूटान नरेश का किया स्वागत।
- **05 फरवरी :** पीएम मोदी के आगमन पर किया स्वागत, त्रिवेणी संगम का पूजन।
- **16 फरवरी :** जलवायु सम्मेलन में सहभागिता, प्रदीप मिश्रा की कथा और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के समापन समारोह में सम्मिलित हुए।

लखनऊ से भी रहे एक्टिव

- **29 अक्टूबर :** केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ लखनऊ में महाकुम्भ से संबंधित पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा।
- **11 जनवरी :** लखनऊ में महाकुम्भ को लेकर परिवहन विभाग की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
- समस्त अमृत स्नान, स्नान पर्वों पर अपने सरकारी आवास पर तड़के से ही रियल टाइम मॉनिटरिंग, उच्च अधिकारियों को दिया निर्देश।

त्रिवेणी के अमृत जल से स्नान कर पुण्य के भागीदार बने प्रदेश की जेलों में बंद कैदी

प्रयागराज की दोनों जेलों में 2400 से अधिक कैदियों ने किया त्रिवेणी जल से स्नान

सचिन तोमर

प्रयागराज महाकुम्भ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए संगम आने वालों का आंकड़ा 59 करोड़ पहुंच गया है। इस अमृत काल में पुण्य की डुबकी से कोई छूट न जाए, सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश की जेल में बंद कैदियों के लिए भी बड़ी पहल की है। प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल और जिला जेल के हजारों कैदियों को भी इसका अवसर मिला। यह पावन अवसर पाकर कैदी भाव विभोर हो गए।

प्रदेश की सभी 62 जेलों के कैदियों ने त्रिवेणी के पुण्य जल से स्नान किया

प्रयागराज महाकुम्भ में पुण्य की डुबकी लगाने को उमड़ रहे आस्था के जन सैलाब ने अब तक के सभी पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रशासन द्वारा आज जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक महाकुम्भ में करीब 59 करोड़ लोग संगम में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में जेल में बंद कैदियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अब उन्हें भी इस पुण्य के भागीदारी बनने का अवसर दिया है। प्रदेश की सभी 62 जेलों के कैदियों ने त्रिवेणी के पुण्य जल से स्नान किया है।

इसके लिए जेल के अंदर ही बड़े-बड़े हौज बनाए गए, जिसमें त्रिवेणी से लाया गया पवित्र जल मिलाया गया। इसी जल से स्नान कर जेल में बंद कैदी भी पुण्य के भागीदारी बने हैं। प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल में भी इसके लिए भव्य व्यवस्था की गई। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल बताते हैं कि नैनी जेल में इस समय 1700 से कैदी है इन्हें 1400 से अधिक कैदियों को त्रिवेणी के पावन जल से स्नान का अवसर मिला है। शासन के निर्देश पर त्रिवेणी से एक कलश में वहां का पावन जल लाया गया। जेल के अंदर विधि विधान से उसका पूजन किया गया और फिर इसी जल को जेल के अंदर बनाए गए कुंड में डाल दिया गया। इसी जल से जेल के कैदियों ने पुण्य स्नान किया है।

बंदियों को भी मिला पुण्य अवसर

प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल के अलावा जिले की जिला जेल के बंदियों को भी अमृत काल में संगम के पुण्य जल से स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करने का अवसर मिला। प्रयागराज जिला जेल की वरिष्ठ अधीक्षक अमिता दुबे बताती हैं कि जेल में वर्तमान में 1300 से अधिक बंदी हैं। इनमें 1000 से अधिक बंदियों को महाकुम्भ के जल से पुण्य स्नान के लिए व्यवस्था की गई। संगम से लाए गए पवित्र जल को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उसी जल से कैदियों ने पुण्य स्नान किया है।

भाव विभोर हुए कैदी, जेल में हुआ हर हर गंगे का हुआ उद्घोष

जेल में बंद इन कैदियों ने संभवतः कभी सोचा भी न होगा कि सलाखों के अंदर रहते हुए भी उन्हें 144 साल के इस दुर्लभ संयोग में त्रिवेणी के पावन जल में स्नान का अवसर मिल पाएगा। लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने कैदियों के लिए इसकी व्यवस्था कर दी। इन कैदियों की त्रिवेणी में ले जाकर स्नान कराने की कानूनी और सुरक्षा की समस्याओं को देखते हुए जेल के अंदर ही इनके त्रिवेणी के पावन जल से स्नान की व्यवस्था की गई। जैसे ही त्रिवेणी से मंगवाए गए जल से इन कैदियों ने पुण्य स्नान किया कैदियों के हर हर गंगे के उद्घोष से पूरा जेल परिसर गूंज गया। उत्तर प्रदेश की जेलों में वर्तमान में लगभग 90 हजार बंदी निरुद्ध हैं।

90 देशों से बड़ी है महाकुम्भ की अर्थव्यवस्था

प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ 2025 न केवल आस्था और भक्ति का महासंगम है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी एक विश्वस्तरीय आयोजन बन चुका है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो इस वर्ष महाकुम्भ से होने वाली अनुमानित आर्थिक गतिविधि 46 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। जीडीपी का यह आंकड़ा दुनिया के 90 देशों की जीडीपी से भी अधिक है। लगभग 90 देश ऐसे हैं जिनकी सालाना जीडीपी 46 बिलियन डॉलर से कम है, जबकि महाकुम्भ में यह आंकड़ा महज 45 दिनों में ही पहुंच गया। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सनातन अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि मूल्य स्वाभाविक रूप से स्थिर होता है। जब इसे गतिशील किया जाता है, तभी यह मूल्य निर्माण कर वास्तविक लाभ प्रदान करता है। महाकुम्भ के इसी आर्थिक सामर्थ्य को गतिशील कर इसमें मूल्य निर्माण का कार्य किया सीएम योगी ने। उन्होंने इस अंतर्निहित आर्थिक क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आज इसका परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहा है।

सीएम योगी ने महाकुम्भ की आर्थिक क्षमता पर डाली दृष्टि और इसे साकार भी किया

सीए पंकज गांधी जायसवाल के अनुसार, महाकुम्भ 2025 से ₹4 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होने की संभावना है, जो भारत की जीडीपी में 1% से अधिक का योगदान देगा। धर्म से अर्थ का संगम बना यह महाकुम्भ अब एक वैश्विक मॉडल बन चुका है। दुनिया को इसने सिद्ध किया है की भारत की उत्सवधर्मिता भारत का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन है जो भारत में कभी मंदी आने ही नहीं देता। यह उत्सवों के माध्यम से समाज में अर्थ ऊर्जा का संचार करता रहता है।

भारत दुनिया का सबसे किफायती और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल

प्रयागराज के सीए अनिल गुप्ता ने बताया कि भारत में धार्मिक पर्यटन न केवल किफायती है, बल्कि इससे होने वाली आर्थिक गतिविधि कई देशों की कुल जीडीपी से अधिक होती है। महाकुम्भ जैसे भव्य आयोजनों से देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। इसी का प्रतिफल महाकुम्भ की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। कानपुर के सीए सुधीर निगम ने बताया कि महाकुम्भ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए एक बूस्टर डोज है। इस आयोजन से पर्यटन, होटल इंडस्ट्री, परिवहन, स्थानीय व्यवसाय और रोजगार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। वाराणसी के सीए और आईसीएआई के उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि महाकुम्भ 2025 ने यह साबित कर दिया है कि भारत में धार्मिक पर्यटन सबसे सशक्त माध्यम है जो अपने साथ कई उद्यमों को समेटे भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकता है। जहां कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संवारने में संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत का यह धार्मिक आयोजन विश्वस्तरीय आर्थिक योगदान देने में सक्षम है।

इन देशों की जीडीपी से अधिक है महाकुम्भ की कमाई

बहरीन –	46.08 बिलियन डॉलर	मालदीव –	6.59 बिलियन डॉलर
कंबोडिया –	42.34 बिलियन डॉलर	लीबिया –	45.10 बिलियन डॉलर
मॉरिशस –	14.64 बिलियन डॉलर	नेपाल –	40.91 बिलियन डॉलर

महाकुम्भ में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने फहराई सनातन की धर्म ध्वजा

- कई देशों की आबादी से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 45 दिन में किया अमृत स्नान
- अमेरिका की दोगुनी से ज्यादा और पाकिस्तान की ढाई गुना से अधिक आबादी ने लगाई पावन डुबकी
- रूस की चार गुनी और जापान की 5 गुनी से अधिक आबादी महाकुम्भ में स्नान करने पहुंची
- यूके की 10 गुनी और फ्रांस की 15 गुनी से ज्यादा जनसंख्या ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान
- दुनिया के 60 प्रतिशत से सनातन धर्मावलंबियों ने संगम स्नान कर बनाया ऐतिहासिक कीर्तिमान

रवि जैन

तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहे दिव्य-भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुम्भ ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 65 करोड़ का आंकड़ा पारकर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महारिकॉर्ड को स्थापित कर इस महाकुम्भ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। कुम्भ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे हैं, जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। यह संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना अधिक है। 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम कर दी है। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुव्यवस्थित प्रयासों से संभव हो पाया है।

कई देशों की आबादी से ज्यादा लोग कर गए स्नान

65 करोड़ श्रद्धालुओं के किसी एक स्थान पर जुटने का इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, दृढ़ निश्चय और विश्वास का ही यह फल है कि संगम तट पर इतना विशाल जनसमूह 45 दिनों में एकत्र हो गया। यदि इस संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। अमेरिका की दोगुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की ढाई गुना से अधिक और रूस की चार गुनी से

ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहां अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुनी आबादी, यूके की 10 गुनी से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 15 गुनी से ज्यादा आबादी ने यहां आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है।

देश की लगभग आधी आबादी ने लगाई डुबकी

तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित इस महाकुम्भ में संख्या के लिहाज से भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यदि देश की

कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो इसके अनुसार भी लगभग 50 प्रतिशत भारत ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली है। वहीं अगर सनातन धर्मावलंबियों की बात करें तो देश के 60 प्रतिशत से ज्यादा और दुनिया के करीब 55 प्रतिशत सनातनी श्रद्धालुओं ने पावन स्नान कर लिया है। 45 दिन तक चले इस आयोजन में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु जुटे हैं। 73 देशों के राजनयिकों के साथ भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत तमाम देशों के अतिथि यहां अमृत स्नान करने पहुंचे। यही नहीं, मां जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से अधिक लोग अब तक त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर महाकुम्भ के साक्षी बन चुके हैं। इसके अलावा इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरीसस समेत दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं.

सीएम योगी की उम्मीदों के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा

मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओत-प्रोत साधु-संतों, श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर के भी पार पहुंच गया है, जिसकी महाकुम्भ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुम्भ का आयोजन हो रहा है वह स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरूआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। हालांकि, श्रद्धालुओं की संख्या सीएम योगी के अनुमान से भी आगे निकल गई। बीती 11 फरवरी को ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो गया, जबकि 22 फरवरी को यह संख्या 60 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। महाशिवरात्रि पर 65 करोड़ की संख्या पारकर इसने नया कीर्तिमान बना दिया।

आखिर कौन, कैसे और कब तक पाएगा भीड़ से उत्पन्न भगदड़ पर काबू ?

लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। तभी ट्रेन सम्बन्धी उद्घोषणा के बाद प्लेटफार्म पर अफरातफरी और भगदड़ मच गई। ऐसे में सवाल है कि देश की राजधानी नई दिल्ली जैसे मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन ने समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की थी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी शनिवार की रात प्रयागराज महाकुंभ जाने को उतावली भीड़ ने ऐसी भगदड़ मचाई कि लगभग डेढ़ दर्जन लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनाधिक घायल भी हुए। इस बार भी मृतकों में महिलाओं (10) और बच्चों (3) की संख्या ज्यादा रही, जबकि पुरुषों (2) की संख्या उनसे कम रही। वहीं, दर्जनाधिक घायलों में भी लगभग 14 महिलाएं समेत कुल 25 लोग शामिल हैं। ये महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी संवेदनाशून्य व्यवस्था की विफलता के नमूने मात्र हैं। ऐसी घटनाओं पर आखिर कौन, कैसे और कबतक काबू पाएगा, यह यक्ष प्रश्न ब्रेक के बाद पुनः समुपस्थित है।

ऐसा इसलिए कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में भगदड़ के कई मामले सामने आए हैं। वहीं, इस बार तो महज एक महीने के अंदर ही भगदड़ के दो-दो

मुकुल पंडित

मामले सामने आ चुके हैं, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। सवाल है कि जब महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तरप्रदेश प्रशासन लगातार डींगें हांक रहा था और केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, तब ऐसी हृदयविदारक घटनाओं का घटित होना उसकी तमाम व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा जाता है। सवाल यह भी है कि तमाम सकारात्मक राजनीतिक इच्छाशक्ति के बावजूद इतनी बड़ी प्रशासनिक चुकें कैसे हो गईं।

हैरत की बात तो यह है कि प्रारम्भिक तौर पर मीडिया माध्यमों में रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी ऐसी किसी घटना व हताहतों के बारे में इंकार कर रहे थे, लेकिन सच्चाई अंत में उन्हें भी बयां करनी ही पड़ी। इससे समझा जा सकता है कि उनका सूचना तंत्र कितना विफल या फिर लोकहित विरोधी है। भले ही इन घटनाओं पर बड़े नेतागण और अधिकारियों के द्वारा खेद प्रकट किया गया हो, जिनके पास वैध टिकट होंगे, उन्हें रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल से मुआवजे भी मिल जाएंगे। लेकिन इससे उन परिवारों की व्यथा कम नहीं हो जाती, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या फिर जिनके परिजन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

बताया गया है कि सभी लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। तभी ट्रेन सम्बन्धी उद्घोषणा के बाद प्लेटफार्म पर अफरातफरी और भगदड़ मच गई। ऐसे में सवाल

है कि देश की राजधानी नई दिल्ली जैसे मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन ने समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की थी। अब भले ही इसकी जांच होगी, पर परिणाम ढाक के तीन पात जैसे ही होंगे!

जाहिर है कि भीड़ और भगदड़ में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध है। लेकिन इनके नियंत्रण के समुचित उपाय कब तक दिखेंगे, किनके नेतृत्व में सब होगा, कुछ पता नहीं। तब तक ब्रेक के बाद होने वाले हादसों पर सवाल उठाते रहिए, चुनाव दर चुनाव राजनीतिक नेतृत्व बदलते रहिए, लेकिन ये अधिकारी हैं, जिनका सिर्फ तबादला होगा। क्योंकि उनकी जानलेवा लापरवाहियों के बावजूद उन्हें जिम्मेदार ठहराने के कानूनी प्रबंध नदारत हैं।

बता दें कि गत 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या से ठीक पहले भी एक दुःखद भगदड़ मची थी, जहां लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 60 लोग घायल हो गए थे।

दरअसल, महाकुंभ मेले में ये हादसा 29 जनवरी के तड़के हुआ था, जब सभी लोग संगम नोज की तरफ नहाने के लिए जा रहे थे। तब यहां भी लाखों लोगों की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। जिसके बाद आनन-फानन में वीवीआईपी व्यवस्था बदल दी गई और अखाड़ों ने भी मौनी अमावस्या के लिए अपने पारंपरिक 'अमृत स्नान' को रद्द कर दिया और दोपहर बाद 'अमृत स्नान' किया। इससे भी धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन सम्बन्धी सवाल उठे थे। यहां भी एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करके प्रशासनिक खाना पूर्ति कर दी गई है। इसलिए भीड़ नियंत्रण सम्बन्धी विफलताओं पर जनसामान्य की चिंता ज्यादा बढ़ गई है।

वहीं, गत 8 जनवरी, 2025 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ में कम से कम 6 भक्तों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे, क्योंकि सैकड़ों लोग तिरुमाला पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे। बताया गया था कि तब 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए देश भर से सैकड़ों भक्त यहां आए थे।

यदि आप पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुई प्रमुख भगदड़ की घटनाओं की सूची खंगालेंगे तो पता चलेगा कि साल-दो साल बाद ऐसी घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। यदि पिछले दो दशकों की प्रमुख भगदड़ सम्बन्धी घटनाओं पर गौर करें तो 27 अगस्त, 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान जहां 39 लोगों की मौत हो गई थी वहीं, 140 अन्य घायल हो गए थे। इसी प्रकार 25 जनवरी, 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई शहर स्थित मंधारदेवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 300 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 अन्य लोग घायल हो गए थे।

वहीं, 3 अगस्त, 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 162 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। तब यहां पहाड़ी की चोटी पर स्थित नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाह के कारण मची भगदड़ मच गई थी। वहीं, 30 सितंबर, 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान भगदड़ मचने पर 250 लोगों की मौत कुचले जाने से हो गई थी। क्योंकि इस दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्री इकट्ठा हुए थे।

वहीं, 4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में 63 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। इस मंदिर में मुफ्त भोजन और कपड़े के लिए हुई भारी भीड़ के कारण भगदड़ हुई थी। इसके अलावा, 15 जनवरी, 2011 को केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के घर जा रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 सबरीमाला भक्त स्वर्गलोक सिधार गए थे, जबकि 40 से अधिक घायल हो गए थे।

इसके अलावा, 8 नवंबर, 2011 को उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाट स्थित हर-की-पौड़ी में 20 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 19 नवंबर, 2012 को पटना के अदालत घाट पर एक अस्थायी पुल पर भीड़ के चढ़ जाने से उसके ढह जाने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, फरवरी 2013 को उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के सबसे व्यस्त दिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में कम से कम 36 हिंदू तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। मृतकों में 27 महिलाएं थीं, जिनमें एक आठ साल की बच्ची भी शामिल थी।

वहीं, 13 अक्टूबर, 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास मची भगदड़ में

115 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। तब यहां मंदिर में देवी दुर्गा की नौ दिवसीय पूजा-अर्चना के लिए 1,50,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। वहीं, 3 अक्टूबर, 2014 को पटना के गांधी मैदान में 30 लोगों की मौत हो गई थी तथा 26 अन्य लोग घायल हो गए थे।

इसी प्रकार, 14 जनवरी, 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में गोदावरी नदी के तट पर मची भगदड़ में 26 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 1 जनवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत ऐसी ही एक जानलेवा भगदड़ में हो गई थी। वहीं, 31 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रामनवमी समारोह के दौरान मची एक भगदड़ में लगभग 36 लोगों की मौत हो गई थी।

वहीं, 2 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक समागम में मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 अन्य लोग घायल हो गए थे। पीड़ित हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा थे जो धार्मिक उपदेशक भोले बाबा के 'सत्संग' के लिए सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव के पास एकत्र हुए थे।

ऐसे में उठता है कि आखिर में भगदड़ क्या है? तो जवाब होगा कि कहीं पर भी अचानक भीड़ के बढ़ने के बाद किसी वजह से मची अफरातफरी से भगदड़ होती है। इस दौरान लोगों का एक बड़ा ताकतवर समूह अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर कमजोर लोग कुचल जाते हैं, कुछ का दम घुट जाता है और मृत्यु हो जाती है। यह घबराहट या उत्तेजना से प्रेरित होती है। यह अफवाहों, भय, सीमित स्थान या अचानक आंदोलनों के कारण उत्पन्न हो सकता है, जिससे भीड़ का व्यवहार अव्यवस्थित हो सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में 79% भगदड़ें धार्मिक आयोजनों के दौरान ही हुई हैं।

सवाल है कि किसी भी भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारक क्या-क्या होते हैं? तो जवाब होगा कि संरचनात्मक विफलताएं यानी कमजोर अस्थायी संरचनाएं, खराब बैरिकेडिंग और संकीर्ण प्रवेश/निकास द्वार अमूमन खतरे पैदा करते हैं। वहीं, भीड़ पर अपर्याप्त नियंत्रण भी प्रमुख कारक हैं, क्योंकि भीड़ के आकार का कम आंकलन, स्टाफ की कमी, अपर्याप्त निकास और अनियंत्रित प्रवेश के कारण भीड़भाड़ हो जाती है। वहीं, घबराहट और अफवाहें की इसकी प्रमुख कारक हैं, क्योंकि झूठे अलार्म या सामूहिक उन्माद के कारण अचानक हलचल हो सकती है, जिससे लोग भागकर गिर जाते हैं और दबे-कुचले जाते हैं।

वहीं, आग एवं विद्युत संबंधी समस्याएं भी कभी कभी इसका कारक बन जाती हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट,

अग्निशामक यंत्रों की कमी या खराब प्रकाश व्यवस्था से भी घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है। वहीं, समन्वय का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारक है, क्योंकि एजेंसियों के बीच खराब योजना, विलंबित प्रतिक्रिया और वास्तविक समय की निगरानी का अभाव ऐसे अप्रत्याशित संकट को और बदतर बना देता है।

यही वजह है कि किसी भी सम्भावित जगह पर भगदड़ रोकने हेतु एनडीएमए ने कतिपय दिशानिर्देश जारी किए होते हैं, फिर भी आधिकारिक लापरवाही या पेशेवर अनुभवहीनता के चलते ऐसी घटनाओं पर अब तक लगाम नहीं लगाया जा सका है। इस निमित्त भीड़ का आकलन और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लिहाजा, प्राधिकारियों को अपेक्षित भीड़ का आकलन करना होता है, प्रवेश बिंदुओं को नियंत्रित करना होता है, तथा लोगों की संख्या को विनियमित करना होता है। वहीं, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा उपाय के सम्बन्ध में मजबूत बैरिकेड्स, आपातकालीन निकास और पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाता है।

वहीं, सुरक्षा और निगरानी उपायों के तहत भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाती है। वहीं, आपातकालीन तैयारी के तहत त्वरित प्रतिक्रिया के लिए चिकित्सा दल, एम्बुलेंस और अग्निशमन इकाइयों को रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है। वहीं, जन जागरूकता और सूचना प्रसार को त्वरित गति से फैलाया जाता है ताकि घबराहट की स्थिति से बचने के लिए लोग साइनबोर्ड, हेल्पलाइन नंबर और वास्तविक समय डिजिटल अपडेट के माध्यम से सजग हो जाएं। इसलिए वहां उपस्थित लोगों को शिक्षित करना प्रमुख प्रशासनिक कार्य होता है।

कहना न होगा कि किसी भी भगदड़ को रोकने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं, जिसमें अनियंत्रित भीड़, अपर्याप्त कानून प्रवर्तन, खराब बुनियादी ढांचे का रखरखाव, प्रौद्योगिकी एकीकरण का अभाव, पूर्व-पंजीकरण प्रणाली का विरोध आदि प्रमुख हैं। जहां तक अनियंत्रित भीड़ का सवाल है तो धार्मिक भावनाएं, अनुशासन की कमी और अचानक भीड़ के बढ़ने से भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। वहीं, अपर्याप्त कानून प्रवर्तन अंतर्गत प्रशिक्षित कार्मिकों की

कमी, समन्वय का अभाव तथा क्षेत्रवार खराब तैनाती प्रतिक्रिया आदि नेक प्रयासों में बाधा डालती है। वहीं, खराब बुनियादी ढांचे का रखरखाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि संकीर्ण मार्ग, कमजोर पुल और अवैध अतिक्रमण बाधाएं पैदा करते हैं। जहां तक प्रौद्योगिकी एकीकरण के अभाव की बात है तो वास्तविक समय भीड़ विश्लेषण, जीपीएस ट्रैकिंग और एआई-आधारित भीड़ नियंत्रण प्रणालियों की अनुपस्थिति से संकट प्रतिक्रिया में देरी होती है। वहीं, पूर्व-पंजीकरण प्रणाली का विरोध वाकई एक जन संकट है, क्योंकि कई तीर्थयात्री अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण का विरोध करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित भीड़ और अत्यधिक क्षमता की समस्या उत्पन्न होती है।

सवाल है कि जब सख्त पूर्व-पंजीकरण और टिकटिंग से इसे रोका जा सकता है तो प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रवेश सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण लागू करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं, यदि उन्नत एआई-आधारित निगरानी प्रणाली का अविलंब उपयोग शुरू हो जाए तो वास्तविक समय भीड़ विश्लेषण, वृद्धि की भविष्यवाणी और भीड़भाड़ को रोकने के लिए एआई और ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। वहीं, सुरक्षा एवं स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देकर भी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए भीड़ मनोविज्ञान और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में विशेषज्ञता वाले अच्छी तरह प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। वहीं, कुशल यातायात और आवागमन योजना लागू करना भी जरूरी है। क्योंकि क्षेत्र-आधारित भीड़ प्रबंधन, एक-तरफा आवागमन मार्ग और अलग आपातकालीन लेन लागू करके इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। वहीं, आपातकालीन मॉक ड्रिल से संकट की स्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों, सुरक्षा और जनता को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से भगदड़ प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित करें। क्योंकि एनडीएमए कहता है कि, 'रोकथाम इलाज से बेहतर है।' यानी भविष्य में भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय भीड़ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सख्त विनियमन महत्वपूर्ण हैं।

लिहाजा, प्रभावी नीति कार्यान्वयन और समन्वय से लोगों की जान बचाई जा सकती है और सुरक्षित सार्वजनिक समारोह सुनिश्चित किए जा सकते हैं। हालांकि, अनुभव बताता है कि इस बाबत जनजागृति बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को कुचलने वाले क्रूर मनुष्य ही होते हैं। क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए तमाम तकनीकी उपाय सुनिश्चित किए थे, बावजूद इसके संगम नोज पर हृदयविदारक घटना घट गई। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्य दबाव कम किया जाए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस देकर जनहितकारी कार्रवाई कर सकें।

सुरक्षा और निगरानी उपायों के तहत भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाती है। वहीं, आपातकालीन तैयारी के तहत त्वरित प्रतिक्रिया के लिए चिकित्सा दल, एम्बुलेंस और अग्निशमन इकाइयों को रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है।

माता-पिता की सेवा से ही सन्तान का जीवन सुखी व सफल होता है

अरुण मिश्रा

हम इस संसार में माता-पिता के द्वारा जन्म प्राप्त कर यहां आये हैं। यदि हमारे माता-पिता न होते तो हमारा जन्म नहीं हो सकता था। हमारे जन्म की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे माता-पिता को अनके प्रकार के कष्ट उठाने तथा पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। यह ऐसा कार्य है कि जो कोई किसी दूसरे के लिये नहीं करता व कर सकता है। हमारा जन्म पूर्वजन्म में मनुष्य या किसी अन्य योनि में मृत्यु होने के पश्चात अपने कर्माशय को भोगने के लिये होता है। ईश्वर का विधान है कि मृत्यु होने पर जीवात्मा पुराना शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर सहित शरीर से बाहर आ जाती है और जन्म प्राप्ति हेतु ईश्वर की प्रेरणा से अपने कर्माशय के योग्य माता-पिता के शरीरों में मनुष्यादि किसी योनि में जन्म ग्रहण करने के लिए प्रवेश करती है वा माता के गर्भ में स्थित होती है। माता को अपनी सन्तान की रक्षा में अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिससे स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके। यदि माता से कोई असावधानी हो जाये तो इससे भावी सन्तान को अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। दस मास गर्भ में रहकर मनुष्य का जन्म शिशु के रूप में होता है। नवजात शिशु रोने के अलावा अपना कुछ काम नहीं कर सकता। माता को अपनी सन्तान की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। वह उसे दुग्धपान कराने सहित उसको स्नान व निद्रा कराके उसका पोषण आदि करती है। उसका मल-मूत्र साफ करती है तथा अनेकानेक विघ्नों से उसकी रक्षा करती है।

दस माह तक अपने गर्भ में रखकर अपनी सन्तान को जन्म देने तक माता को अनेकानेक कष्ट उठाने पड़ते हैं जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सब कार्य सब मातायें अपनी सन्तान के सुख व उन्नति के लिये करती हैं। उसके बाद भी सन्तान की शिक्षा, रक्षा व पालन पोषण करने में माता को विशेष ध्यान देना पड़ता है। वर्षों तक की माता-पिता की तपस्या के बाद सन्तानें कुछ ज्ञान व धनोपार्जन का कार्य करने में समर्थ होती हैं। ऐसा करते हुए माता-पिता की आयु बढ़ती जाती है और वह प्रौढ़ व वृद्ध हो जाते हैं। उनके जीवन का युवावस्था का स्वर्णिम समय सन्तान की रक्षा, पालन पोषण व उनकी शिक्षा-दीक्षा में ही व्यतीत हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ माता पिता के शरीर भी बलहीन होते जाते हैं और आजकल अनेक रोग भी कुछ माता-पिताओं को हो जाते हैं। प्रौढ़ व रुग्ण अवस्था में उनको अपने युवा सन्तानों की सहायता व सेवा की आवश्यकता पड़ती है। यह सहायता व सेवा सन्तान का कर्तव्य व धर्म होता है। प्राचीन काल से हमारे देश में वैदिक संस्कारों का प्रचलन रहा है। सब देशवासी संयुक्त परिवार में रहते थे और किसी को किसी प्रकार का कष्ट व दुःख होने पर एक दूसरे की सेवा करते थे।

सन्तानें भी अपने माता-पिता की सेवा को अपना मुख्य धर्म व कर्तव्य समझती थीं परन्तु देश की आजादी के बाद देश में जो अंग्रेजी व स्कूली शिक्षा को लाया गया उससे सन्तानों में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा भी देखने को मिलती है। आजकल सन्तानें माता-पिता की वह सेवा नहीं कर पाती जैसी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। जो कुछ करती हैं वह धन्य हैं और जो नहीं करती उन्हें अपने आचार व विचारों में सुधार करना चाहिये।

जो सन्तानें वर्तमान समय में अपने माता-पिता की सेवा व सहायता की उपेक्षा करती हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करतीं, उन्हें याद रखना चाहिये कि भविष्य में उन्हें भी माता-पिता बनना है और उनके साथ भी वैसा कुछ हो सकता है जैसा कि वह अपने माता-पिता आदि की उपेक्षा करके करते हैं। अतः संतानों को आरम्भ से ही उनके कर्तव्यों का बोध घरेलु व स्कूली शिक्षा में कराया जाना आवश्यक है।

यदि उन्हें माता-पिता की सेवा विषयक संस्कार नहीं दिये जायेंगे तो बड़े होने पर कुछ कानून आदि बनाकर भी उनसे सेवा नहीं कराई जा सकती। जो सन्तानें अपने माता पिता की सेवा के स्थान पर उनकी उपेक्षा करती हैं, उनसे माता-पिता को सामर्थ्यवान होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं जिससे उनका जीवन चिन्ताओं व कष्टों में व्यतीत होता है।

अतः धर्म व समाज शास्त्रियों को इस समस्या पर विचार कर उसके निवारण में कार्य करना चाहिये जिससे प्रौढ़ व वृद्धावस्था में माता-पिता सुख का जीवन व्यतीत कर सकें।

वैदिक धर्म एवं संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन वा आदि संस्कृति है। वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञान वेदों से हुआ है। वेदों में माता, पिता तथा आचार्य को देवता कहा गया है। देवता वह होता है जो अनायास, बिना किसी प्रत्युपकार की भावना से दूसरों को कुछ न कुछ देता है। जड़ देवताओं पर विचार करें तो अग्नि, वायु, जल, अन्न, भूमि सहित गो आदि चेतन आत्माओं से युक्त पशुओं से हमारा जीवन चलता है। यदि यह पदार्थ न हों तो हम जीवित नहीं रह सकते। इस लिये वेदों में इन सब पदार्थों को जिनसे हमें सुख प्राप्ति व हमारा पोषण होता है, देवता कहा जाता है। जड़ देवताओं के अतिरिक्त गो आदि चेतन देवताओं में परमात्मा के बाद माता, पिता तथा आचार्य आदि का स्थान आता है। जीवित देवताओं में सन्तानों के सर्वाधिक पूजनीय, आदरणीय व आज्ञाओं का पालन करने योग्य माता, पिता व आचार्यों का स्थान होता है। मनुस्मृति के एक श्लोक में कहा गया है कि जहां नारियों वा माताओं के प्रति सद्व्यवहार होता है, वहां नारियां प्रसन्न व सन्तुष्ट रहती हैं तथा वहां उन परिवारों में सन्तान के रूप में देवता निवास करते हैं। यह देवता बचपन से ही देव बनकर आजीवन वृद्धावस्था पर्यन्त भी देव बने रहते हैं। अतः नारी जाति को वैदिक शिक्षाओं से युक्त, धर्म पारायणा तथा अपने कर्तव्यों के पालन में सजग व जागरुक रहना आवश्यक होता है। तभी वह गरिमा को प्राप्त हो सकती हैं।

वेदों की एक अत्यन्त उपादेय शिक्षा है कि भाई को भाई से, बहिन को बहिन से तथा भाई व बहिनों को भी परस्पर द्वेष भाव नहीं रखना चाहिये। सब भाई बहिन आपस में मित्रवत्प्रेम व स्नेह के व्यवहार से आबद्ध रहें। ऐसा करने पर ही मनुष्य व परिवार की उन्नति व सुखों में वृद्धि होती है। इस बात को सिद्धान्त रूप में प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करता है परन्तु यह व्यवहार में देखने में नहीं आतीं। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मनुष्यों को अपने वैदिक कर्तव्यों व उनके महत्व का ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा हो और वह इनका अवश्य पालन करें जिससे मनुष्य जीवन से अनेक दुःखों का निवारण हो सकता है। इस अभाव को दूर करने के लिये हमें सबसे अच्छा उपाय यही लगता है कि सभी आर्य व हिन्दू परिवारों में सत्यार्थप्रकाश, उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति, चतुर्वेद भाष्य तथा आर्य विद्वानों के वेद विषयक व्याख्या ग्रन्थों की प्रतिष्ठा होनी चाहिये। सबको नियमित एक से दो घण्टे इन ग्रन्थों का स्वाध्याय करना चाहिये और आर्यसमाज के सत्संगों में भी

सबको जाना चाहिये जहां वैदिक विद्वानों के जीवन के उत्थान व देश की उन्नति के उपदेश होते हैं। सत्पुरुषों वा ज्ञानियों की संगति से मनुष्य को अकथित लाभ होता है। इससे अज्ञानी व निरक्षर मनुष्य भी प्रेरणा ग्रहण कर उच्च कोटि का विद्वान बन सकता है। हमने यहां तक पढ़ा है कि श्मशान घाट में काम करने वाला एक बालक गुरुकुल के आचार्य के सम्पर्क में आकर कालान्तर में बहुत बड़ा विद्वान बन गया जिसकी संगति करने में विद्वान लोग भी अपना गौरव समझते थे। अतः न केवल माता-पिता की सेवा एवं कृतघ्नता से बचने के लिये स्वाध्याय व सत्संग की आवश्यकता है वहीं जीवन का सर्वविध कल्याण करने के लिये भी स्वाध्याय व सत्संग सहित ईश्वरोपासना आदि पंच महायज्ञों का किया जाना आवश्यक सिद्ध होता है।

माता-पिता की आदर्श सेवा का उदाहरण हमें बाल्मीकि रामायण ग्रन्थ का अध्ययन करने से भी मिलता है। राम वैदिक धर्म व संस्कृति के मूर्तरूप थे। उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात किया था। वह प्रातः व सायं अपनी सभी माताओं व पिता की चरण वन्दना व उनका सत्कार किया करते थे। उनका आचरण व व्यवहार आदर्श व्यवहार था। उन्होंने जीवन में अपने पिता व किसी माता को अपने किसी व्यवहार से शिकायत व आलोचना का अवसर नहीं दिया।

इस कर्तव्य परायणता के लिये उन्हें अनेक कष्ट भी उठाने पड़े जिन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। पिता के वचनों का पालन करने तथा माता कैकेयी को सन्तुष्ट करने के लिये ही उन्होंने चैदह वर्ष वन में साधु वेश में रहना स्वीकार किया था। उन्होंने सहर्ष अपने छोटे भाई भरत को अपना राज्य प्रदान किया था जिसके वह स्वयं अधिकारी थे और प्रजा व भाई भी उनको ही राजा के रूप में देखना चाहते थे। ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में मिलना असम्भव है। राम के द्वारा अपने पिता को कहे यह वचन सुनकर तो उनके प्रति श्रद्धा कई गुणा बढ़ जाती है जब वह पिता को कहते हैं कि आप मुझे अपने दुःख का कारण बताईये। यदि आप कहेंगे तो मैं बिना सोचे विचारे जलती हुई चिता में भी कूद कर अपने प्राण दे सकता हूं। क्या इससे बड़ा अपने पिता को सुख देने वाला सर्वस्व त्याग का उदाहरण कहीं मिल सकता है? जो सन्तानें अपने माता-पिता की सेवा-शुश्रुषा से दूर हैं, उन्हें अवश्य ही रामायण व इस प्रकार के उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिये। माता-पिता ने उनके पालन पोषण में दुःख सहन किये हैं उन पर भी सन्तानों को विचार करना चाहियें।

आज के समाज में हम देखते हैं कि शिक्षा व संगति के कारण सन्तानों वा युवा पीढ़ी को माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का यथोचित ज्ञान नहीं है। वह प्रायः स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा सोचना व करना भारतीय वैदिक संस्कृति के सर्वथा विपरीत तथा भोगवादी पश्चिमी संस्कृति की देन है। ऐसा करना जीवन के उत्तर काल में अवश्य दुःख वा क्लेश देता है। अतः हमें अपनी संस्कृति पर पुनः लौटने की आवश्यकता है। हमने अनेक परिवारों में वृद्ध माता-पिताओं से उनके सन्तान-मोह व सन्तानों के माता-पिता के प्रति अप्रिय व्यवहार के कृत्यों को देखा, सुना व अनुभव किया है। इसी कारण हमने इस लेख की इन पंक्तियों को लिखा है। लेख को समाप्त करने से पूर्व हम महाभारत में यक्ष के प्रश्नों के उत्तर में कहे गये युधिष्ठिर जी के वचनों को उद्धृत करना चाहते हैं। राजा युधिष्ठिर में यक्ष को कहा था कि माता पृथिवी से भारी है। पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिन्ता तिनकों से भी अधिक असीम विस्तृत व अनन्त है। युधिष्ठिर के वचन हैं ह्यमाता गुरुतरा भूमेः पिता चोच्चतरं च खात्।ह्ल शास्त्र माता को सन्तान की निमार्ता बताते हैं। महाराज मनु ने कहा है कि दस उपाध्यायों से एक आचार्य, सौ आचार्यों की अपेक्षा एक पिता और हजार पिताओं की अपेक्षा एक माता गौरव में अधिक वा बड़ी है। वैदिक संस्कृति में प्रति दिन जीवित माता-पिताओं की पूजा वा सेवा-सुश्रुषा करने का विधान है। हमने इन श्रेष्ठ परम्पराओं को छोड़कर अपनी भारी क्षति व परजन्म के सुखों का नाश किया है। हमें पुनः वैदिक धर्म व संस्कृति को प्रवृत्त कर जन्म व परजन्म में होनेवाली हानियों से बचना चाहिये। ओ३म

मोदी का मोटापामुक्त भारत स्वास्थ्य-क्रांति का आधार

प्रधानमंत्री मोदी ने सेहत के प्रति जागरूकता लाने और इस क्रम में मोटापे से लड़ने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के दस जाने-माने लोगों को नामांकित कर यही रेखांकित किया कि इस समस्या की गंभीरता को समझने एवं समय रहते इसको नियंत्रित करने की अपेक्षा है।

डॉ. निमित त्यागी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में भारतीय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर निरन्तर कदम उठाते हुए स्वस्थ भारत निर्मित करने के उपक्रम किये हैं। विकसित भारत-नये भारत-सशक्त भारत का आधार स्वस्थ भारत ही है। मोदी युग ने स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करते हुए मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने और मोटापे को नियंत्रित पर अधिक ध्यान दिया गया। मोदी ने मोटापे के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें भारतीयों से अपने खाना पकाने के तेल की खपत को कम करने का आग्रह किया। मोटापा कई जीवनशैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जैसे दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, सांस लेने में समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे चिंता, तनाव और अवसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को मन की बात के 119वें एपिसोड में हेल्थ का जिक्र करते हुए कहा था, एक फिट और स्वस्थ भारत बनने के लिए हमें ओबेसिटी (मोटापा) की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक, आज हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते सालों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या चार गुना बढ़ गई है। मोटापे को नियंत्रित करने की मुहिम एक सामयिक एवं सराहनीय कदम होने के

साथ स्वास्थ्य-क्रांति का आधार है।

प्रधानमंत्री ने सेहत के प्रति जागरूकता लाने और इस क्रम में मोटापे से लड़ने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के दस जाने-माने लोगों को नामांकित कर यही रेखांकित किया कि इस समस्या की गंभीरता को समझने एवं समय रहते इसको नियंत्रित करने की अपेक्षा है। उन्होंने आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलेकणि, उमर अब्दुल्ला, आर. माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति को नामांकित करते हुए यह अपेक्षा जताई कि ये सभी मोटापे के खिलाफ क्रांति की अलख जगाने के साथ खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इन लब्ध प्रतिष्ठित हस्तियों से दस-दस और लोगों को इसी अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नामांकित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री की यह पहल कुछ वैसी ही है, जैसी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करते समय की थी। मोदी की मोटापे नियंत्रण से जुड़ी इस जनोपयोगी पहल से देश मे मोटापे के प्रति चेतना जाग्रत होगी और लोग मोटापे को नियंत्रित करने में सफल होंगे।

मोटापा वर्तमान युग की एक व्यापक स्वास्थ्य समस्या एवं एक दीर्घकालिक बीमारी है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं एवं असाध्य बीमारियों का कारण बन सकती है और आपके जीवन को छोटा कर सकती है। दुनिया भर में मोटापे के शिकार एक अरब से ज्यादा लोगों में 88 करोड़ लोग वयस्क हैं जबकि 15 करोड़ 90 लाख बच्चे हैं। महिलाओं में मोटापा बढ़ने की सबसे तेज गति देखने को मिल रही है। आज मोटापा समस्या नहीं महामारी बन गया है। मोटापे ने महामारी का ऐसा रूप धारण किया कि इसने भुखमरी को भी पीछे छोड़ दिया है। भूखमरी से जितनी मौतें होती हैं उससे कई ज्यादा मौतों की वजह अब मोटापा बन गया है। यूएन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 5 से 9 साल के बीच के 13.1 करोड़ बच्चे, किशोरावस्था वाले 20.7 करोड़ और 200 करोड़ वयस्क लोग मोटापे के शिकार है।

अच्छी सेहत के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है, सेहत ठीक नहीं होगी तो व्यक्ति दुखी, तनावग्रस्त और रोगी बना रहता है। सेहत ही सबसे बड़ा धन है। ये बात जो लोग समझते हैं, वे अपनी सेहत के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बाधा मोटापा है, जब कोई व्यक्ति ऊर्जा के रूप में उपयोग की जाने वाली कैलोरी से अधिक कैलोरी का उपभोग करता है, तो उसका शरीर अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप में संग्रहीत कर लेता है। इसी से मोटापा पनपता है। शारीरिक श्रम की कमी पेट पर मोटापा जमा होने का एक प्रमुख कारण है। आजकल की जीवनशैली में अधिकतर लोग 9-10 घंटों तक एक जगह बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि न के बराबर करते हैं। इससे शरीर में जमा हुई अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करने में कठिनाई होती है और ये कैलोरी मोटापे के रूप में बदल जाती है। तनाव और नींद की कमी भी मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जो पेट के आसपास चर्बी जमा करने का काम करता है। नींद की कमी से मेटाबोलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर अधिक चर्बी जमा करने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा, कुछ खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और पेय पदार्थ-विशेषकर वे जिनमें वसा और शर्करा की मात्रा अधिक होती है-वजन बढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं।

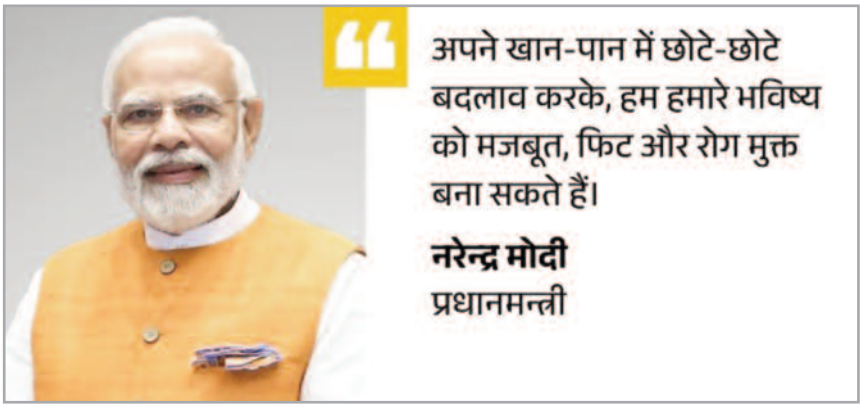

लोगों में मोटापा बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें अति भोजन, अहितकर भोजन और प्रतिकूल भोजन के अलावा व्यायाम की कमी और तनाव शामिल हैं। पोषण में सुधार, गतिविधि बढ़ाने और जीवनशैली में अन्य बदलाव करने से लोगों के मोटापे को कम करने में मदद मिल सकती है। मोदी की पहल से मोटापा नियंत्रित करने के अनुकूल परिणाम तभी सामने आ सकते है, इसमें वांछित सफलता तभी संभव है, जब आम लोग यह समझेंगे कि स्वस्थ जीवनशैली उन्नत राष्ट्र ही नहीं, उन्नत स्वास्थ्य का आधार है। आज की सुविधा एवं भौतिकतापूर्ण जीवनशैली मोटापा बढ़ाने का काम कर रही है। अब लोग उतना शारीरिक श्रम नहीं करते, जितना पहले अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत किया करते थे। मोटापे को नियंत्रित करने में योग, ध्यान, प्रातःभ्रमण एवं व्यायाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी विचारक ने लिखा भी है कि मनुष्य के सबसे बड़े चिकित्सक हैं- शांति, प्रसन्नता और खुराक।ह्न यह हकीकत है कि लोग यदि खानपान में संयम एवं सतर्कता बरतें, शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं और योग-व्यायाम को जीवन का हिस्सा बना लें तो मोटापे को भगा सकते हैं।

मोटापे अनेक बीमारियों का घर है, जो केवल कार्यक्षमता को कम करने का ही काम नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ाता है। जीवन को जटिल एवं अस्तव्यस्त बना देता है। निरोगी लोग किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो लोग मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और वे अपना काम कहीं अधिक तत्परता एवं निपुणता से करते हैं। इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मिलता है। यही सशक्त एवं विकसित भारत का आधार भी है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली की जरूरत को समझा, लेकिन इसके लिए जागरूकता अभियान छेड़ने के साथ ही मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए भी कुछ करना होगा। मोदी की यह पहल जहां स्वास्थ्य क्रांति का माध्यम बनेगी, वहीं मिलावट नियंत्रण के प्रति भी जागरूकता पैदा करेंगी। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री बनती एवं बिकती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा उस खाद्य सामग्री का होता है, जो सड़क किनारे की दुकानों पर मिलती है।

इस सामग्री में केवल खाद्य तेल की मात्रा ही अधिक नहीं होती, बल्कि वह मिलावटी भी होता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी के चलते दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री घरों में भी इस्तेमाल होती है। इनमें खाद्य तेल एवं घी प्रमुख है। आज जब बाजार का खाना खाने का चलन बढ़ रहा है, तब सरकार को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि उसकी शुद्धता एवं गुणवत्ता से कोई समझौता न होने पाए। इसी अभिक्रम से भारत का जन-जन स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ भावनाओं का अखूट वैभव लिये शक्ति, स्फूर्ति, शांति, आनन्द एवं शारीरिक संतुलन से भरपूर दिव्य जीवन की यात्रा के लिये प्रस्थित हो सकता है। इससे हम मोटापा-मुक्त स्वस्थ भारत के संकल्प को हकीकत बना सकते हैं। स्वस्थ भारत का यह संकल्प ही कालांतर विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मददगार हो सकता है।

सेल्फी की चाह में मौत से खेल रहे युवा

आए दिन सामने आ रही दिल दहला देने वाली घटना

संजय बैंसला

शोशल मीडिया के इस दौर में सेल्फी लेने का चलन बेतहाशा बढ़ा है। खासकर युवा एक दिन में कई-कई बार सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर साझा करते हैं।

उच्च गुणवत्ता के कैमरे से लैस मोबाइल फोन अब मौत का सबब बन रहे हैं। बार-बार स्वयं की अच्छी तस्वीर लेने की लत कब बेलगाम भूख में तब्दील होती गई, इसका अहसास तब हो रहा है, जब सेल्फी लेते लोगों, खासकर युवाओं की जिंदगी दांव पर लग गई दिखती है। पिछले कुछ समय से युवा पीढ़ी में इसका नशा इस कदर हावी होता जा रहा है कि वे अपनी फिक्र करना भी जरूरी नहीं समझ रहे। नतीजतन, ऐसा करते हुए कोई झील में डूब जाता है, तो कोई पहाड़ से गिर जाता है या फिर रेलगाड़ी की चपेट में आ जाता है।

सेल्फी के प्रति इतनी दीवानगी की वजह समझने की आवश्यकता है। खुद की खास तस्वीर लेने के फेर में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से नहीं हिचकिचा रहे, तो इसका अर्थ है कि वे ऐसी मानसिक अवस्था में हैं, जो यथार्थ से दूर है। गौरतलब है कि मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा एक युवक यह देख नहीं सका कि कोयना एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही है। रेलगाड़ी की चपेट में आकर हुई इस युवक की मौत इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है।

सोशल मीडिया के इस दौर में सेल्फी लेने का चलन बेतहाशा बढ़ा है। खासकर युवा एक दिन में कई-कई बार सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर साझा करते हैं। यह प्रवृत्ति उनकी मनःस्थिति को दशार्ती है। लंदन की नाटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु के त्यागराज स्कूल आफ मैनेजमेंट के साझा अनुसंधान का निष्कर्ष है कि अगर किसी का दिन भर में तीन से ज्यादा सेल्फी लेने से मन नहीं भरता, तो उसे कोई विकार है।

यह लत अब घातक होती जा रही है, क्योंकि एक आकलन के मुताबिक सेल्फी लेते हुए सबसे ज्यादा मौत इस समय भारत में हो रही है। इसकी वजह सिर्फ स्मृतियों को संजोने तक सीमित नहीं हो सकती। दरअसल, लोग दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं। मगर इस क्रम में अपनी जान गंवा देने तक की लापरवाही बरतने को कैसे उचित माना जा सकता है?

आकांशा गर्ग

हॉलीवुड में भी डंका

भारतीय सिने जगत के कई ऐसे सितारे हैं, जिनका विदेशों में भी डंका बजा है। इनमें अभिनेता ही नहीं, कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी शामिल हैं, जिनके न सिर्फ अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी करोड़ों फैन हैं। कुछ तो सरकार के कूटनीतिक मामलों में भी सहयोगी साबित हुए हैं।

बेशक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के मामले में भारतीय सिने इंडस्ट्री बहुत ऊंचे मुकाम पर न पहुंच पाई हो, लेकिन हमारे देश के कई सिनेस्टार्स विदेशों में भी अपने लाखों-करोड़ों प्रशंसक बनाने में कामयाब हुए हैं। कई बार तो कूटनीतिक मामलों में भी ये स्टार्स सरकार के मददगार साबित हुए हैं। यकीनन इन सिनेस्टार्स की यह उपलब्धि काबिल ए गौर कही जाएगी। इनमें राजकपूर, संजयखान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम उल्लेखनीय हैं। यहां हम कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

राज कपूर

कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले अभिनेता व निमार्ता-निर्देशक स्व. राजकपूर जितने भारत में लोकप्रिय रहे हैं, उससे ज्यादा रूस में उनके दीवाने थे। भारतीय फिल्मजगत के शोमैन कहे गए राजकपूर ने न केवल बड़े अभिनेता और फिल्म निमार्ता के तौर पर नाम कमाया, बल्कि भारतीय सिनेमा को उन्होंने ऐसी कई फिल्में दीं, जिन्होंने आगे आने वाले सिनेमा के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया। राजकपूर

जब भी रूस जाते थे तो उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। उनका वहां ऐसा क्रेज था कि एक बार वे रूस में बिना वीजा के पहुंच गए थे। मॉस्को एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त भीड़ ऐसी थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। वह अपनी कार में जैसे ही बैठे तो फैंस ने उन्हें कार सहित उठा लिया था। जब राज कपूर की फिल्म 'आवारा' सोवियत संघ में रिलीज हुई तो इस फिल्म का मशहूर गाना 'आवारा हूं' सोवियत संघ में रहने वाले हर व्यक्ति की जुबां पर था। जब नेहरू जी अपनी पहली सोवियत यात्रा पर गए तो भीड़ उनका 'आवारा हूं' गीत गाकर स्वागत किया था।

शाहरुख खान

दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारतीय अभिनेता है, तो वह है बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान। भारत समेत दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस समेत दो दर्जन से ज्यादा देशों में उनके फैंस हैं। वहां की सरकारों से भी शाहरुख खान के अच्छे रिश्ते हैं। पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था शाहरुख खान ने साल 2022 में जासूसी के आरोप में पकड़े कए नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर के शाह से रिश्तों के चलते छुड़वाने में अपनी भूमिका निभाई थी। स्वामी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद शाहरुख खान से इस मामले में मदद करने के लिये कहा था। उनके कहने पर शाहरुख कतर गए और वहां के शाह से मुलाकात की। उन्होंने नौसेना के सभी 8 पूर्व अधिकारियों को मुक्त करने के लिए वहां के शेख को मनाने में कामयाबी हासिल की थी। बता दें कि कतर की एक अदालत ने अक्टूबर 2022 में इन पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी।

इरफान खान

दिवंगत अभिनेता इरफान खान एक ऐसे अभिनेता थे, जिनकी एफर्टलेस एक्टिंग ने लाखों दिलों को जीता था। बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी उन्हें बेशुमार प्यार मिला। 'स्लमडॉग मिलियनेयर', 'जुरासिक वर्ल्ड' और 'द अमेजिंग स्पाइडर-मैन' में अपनी भूमिकाओं के लिए इरफान खान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। उनकी फिल्म 'लाइफ ऑफ पाई' में उनकी परफॉर्मेंस की दुनिया भर में तारीफ हुई। दुर्भाग्य से इरफान को मौत ने बहुत जल्दी सुला दिया।

संजय खान

70 के दशक में फिल्म अभिनेता और निर्माता संजय खान भी ग्लोबल स्टार थे। खासकर अरब देशों में उनकी दीवानगी दिखती थी। इन देशों की सरकारों से संजय खान के निजी रिश्ते हुआ करते थे। एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में तत्कालीन सरकार के कहने पर संजय खान ने अरब के शाह से मुलाकात की और भारत को निर्यात होने वाले तेल की कीमतों में कटौती करने का आग्रह किया। आखिर दोस्त के आग्रह का सम्मान करते हुए भारत को भेजे जाने वाले तेल की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती कर दी गई थी। अरब देशों में संजय खान की फिल्में खूब चला करती थीं।

प्रियंका चोपड़ा

मिस वर्ल्ड रहीं प्रियंका चोपड़ा अब विदेशी बहू तो हो ही गई हैं, हॉलीवुड फिल्मों की वे लोकप्रिय हीरोइन भी हैं। प्रियंका ने एक अमेरिकी थ्रिलर टीवी सीरीज 'क्वांटिको' के साथ हॉलीवुड में कदम रखा था। बाद में उन्हें ड्वेन जॉनसन स्टारर फिल्म 'बेवॉच' के अलावा, 'इजन्ट इट रोमांटिक' और 'द मैट्रिक्स रिसेरेक्शन्स' में भी देखा जा चुका है। हॉलीवुड में उनका नाम प्रमुख अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता है।

दीपिका पादुकोण

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म 'गहराइयां' को बेशक मिक्स रिव्यू मिले हैं, लेकिन उनके अभिनय की तारीफ हर किसी ने की है। दीपिका बॉलीवुड की एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने हॉलीवुड में भी अपने चार्म से लोगों को दीवाना बनाया है। दीपिका ने साल 2017 में हॉलीवुड एक्टर विन डिजल के साथ फिल्म '77: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' से हॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी पहली ही फिल्म के बाद उनका नाम हॉलीवुड में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। दीपिका अकेली ऐसी हीरोइन हैं, जो भारतीय परिवेश में जितनी खप जाती हैं, उतनी ही पाश्चात्य में भी। आने वाले दिनों में वें हॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाई देने वाली हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म दर्शकों को आईकॉनिक फिल्में दी हैं। उनकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक्टिंग के भी लोग दीवाने हैं। उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है कि उन्हें हिंदी के साथ अंग्रेजी फिल्मों में भी खूब देखा गया है। उन्होंने हॉलीवुड की 'ब्राइड एंड प्रेजुडिस', 'द लास्ट लीजन', 'प्रोवोक्ड', 'द पिंक पैंथर 2', 'द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस' जैसी फिल्मों में काम कर अपने दमखम का परिचय दिया है।

आमिर खान

अभिनेता आमिर खान को यूं ही परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता। वे अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया भर में करोड़ों फैंस बना चुके हैं। खासकर चीन में आमिर के करोड़ों फैन हैं। चीन में उन्हें 'अंकल खान' का नाम दिया गया है। वे चीन में इतने लोकप्रिय हैं कि चीन सरकार ने वहां के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर तक नियुक्त करने के बारे में सोचा था।

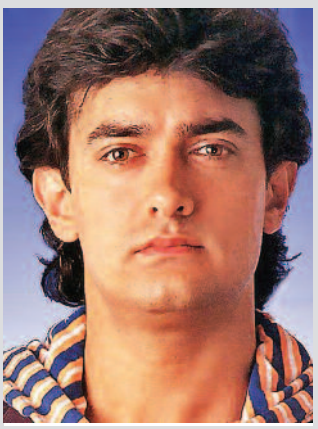

हरेन्द्र शर्मा

अगला कप्तान कौन ?

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके खराब फार्म को देख हर क्रिकेट समीक्षक कहता देखा जा रहा है कि टीम कप्तान बदलना चाहिए। देखते हैं कि आखिर कौन हो सकता है अगला कप्तान ?

क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में शुमार टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों बेहद बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं। उनकी अगुवाई में टीम लगातार हार रही है। रोहित का बल्ला खुद इन दिनों खामोश है। कुछ पूर्व क्रिकेटर्स की राय है कि रोहित को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जिनका तर्क है कि हर खिलाड़ी के साथ एक बार ऐसा ही होता रहा है। वे तर्क दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जब रोहित की फार्म लौटेगी तो सबके मुंह सिल जाएंगे। खद रोहित सन्यास को लेकर तकरीरें कर रहे दिग्गजों को दो टूक कह चुके हैं कि अभी उन्होंने सन्यास के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हालत बेहद पतली रही है। सीरीज में पहला मैच जीतने और दूसरा किसी तरह ड्रा कराने के बाद टीम इंडिया बाकी के सभी मैचों में बुरी तरह परास्त हुई है। पहला मैच बुमराह की कप्तानी में खेला गया था। इसके बाद के मैचों में रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली, लेकिन न सिर्फ वे खुद अच्छा खेल पाए और न उनकी टीम के बाकी बल्लेबाज। सिडनी के आखिरी टेस्ट में एक बार जीत की उम्मीद बंधी थी, लेकिन रोहित समेत सभी भारतीय बल्लेबाज

केएल राहुल

रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल को भावी कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। स्वभाव से गंभीर और अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ ही मौका पड़ने पर अच्छे विकेटकीपर होने का वे प्रमाण देते रहे हैं। टीम के साथ अच्छे व्यवहार के लिये भी उन्हें जाना जाता है। साल 2022 में जब विराट कोहली इंजर्ड थे, तब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने कप्तानी की थी। अगर रोहित टीम से बाहर होते हैं तो केएल राहुल बेहतर ओपनिंग बल्लेबाज माने जा रहे हैं। दिग्गजों का कहना है कि अगर केएल राहुल कप्तान बनेंगे तो मजबूत बैटिंग ऑर्डर भी बन जाएगा। फिलहाल टीम को अच्छी और टिकाऊ ओपनिंग बल्लेबाजी की जरूरत है, जिसमें कुछ समय से रोहित शर्मा असफल साबित हुए हैं।

एक के बाद एक धराशाई हो गए और टीम को सीरीज गंवानी पड़ी। यही नहीं, यह सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के दरवाजे भी बंद हो गए।

जाहिर है कि ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कप्तान रोहित शर्मा के सन्यास लेने का वक्त आ गया है। कई दिग्गजों ने उन्हें सीरीज हारने की मुख्य वजह बताया और रोहित को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दे डाली। अब रोहित सन्यास लेते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि चयनकर्ता उन्हें अब टीम इंडिया की कमान सौंपने का जोखिम नहीं लेंगे और उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम की कप्तानी सौंपी जाएगी। लेकिन आखिर कौन होगा ऐसा नया कप्तान, जो भारतीय टीम को फिर से संभालने में सक्षम होगा? फिलहाल, इसके लिये चार नाम लिये जा रहे हैं।

शुभमन गिल

रोहित शर्मा की जगह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल भी टीम इंडिया की कप्तानी के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। वे जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही वे कई मौकों पर रोहित शर्मा के डिप्टी भी रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ अगस्त 2024 में खेली गई टी-20 इंटरनेशन और वनडे सीरीज में शुभमन गिल ही टीम इंडिया के उपकप्तान थे।

ऋषभ पंत

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पंत को कप्तान बनाने की वकालत की है। उनके मुताबिक पंत फिलवक्त अकेले इस लायक हैं। अपनी दलील देते हुए कैफ कहते हैं कि जब भी पंत खेलते हैं तो टीम इंडिया फ्रंटफुट पर रहती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने शॉट सेलेक्शन के लिए पंत की आलोचना हुई है और कहा गया है कि वे स्वाभाविक खेल के चक्कर में टीम की परिस्थितियों को दरकिनार कर देते हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस बल्लेबाज के खराब शॉट से टेस्ट हार जाए, वह टीम की बागडोर नहीं संभाल सकता। ऋषभ पंत के फेवर में एक बात है कि वे तीनों फार्मेट में बिना किसी विवाद के सेलेक्ट होते रहे हैं पंत की गेम को लेकर समझ और साथी खिलाड़ियों के बीच उनका कद और इज्जत उन्हें कप्तान का दावेदार बनाता दिख रहा है।

जसप्रीत बुमराह

चूंकि आस्ट्रेलिया में हुई सीरीज के पहले मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी, लिहाजा उनका नाम कप्तान की सूची में पहले नंबर पर लिया जा रहा है। बुमराह इस समय दुनिया के नंबर एक तेज गेंदबाज हैं। वे अपनी लगातार फार्म का नमूना भी दिखा चुके हैं और पहला टेस्ट जीतकर होशियार कप्तान होने का सबूत भी दे चुके हैं। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में भी बुमराह ने न केवल कमाल की कप्तानी की, बल्कि अपनी गेंदबाजी का आस्ट्रेलियाई टीम पर कहर भी बरपाया। इन दिनों बुमराह के सितारे बुलंद हैं।

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल भारतीय टेस्ट टीम के स्थायी ओपनर बन चुके हैं। साल 2024 में वे भारत के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने एक साल में 1478 रन बनाकर टीम में अपनी मजबूत जगह बनाई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जायसवाल से भी कप्तानी करवानी चाहिए। हालांकि यह कहने वालों की भी कमी नहीं है कि यशस्वी जायसवाल अभी उतने परिपक्व नहीं हैं कि वे सीनियर खिलाड़ियों की कप्तानी करने में सहज हो सकेंगे। उन्हें कप्तान बनाने से पहले एक-दो साल और अपना स्वाभाविक खेल खेलने देना चाहिए।

HET

Once You
Buy The

Solar

The Power is Free

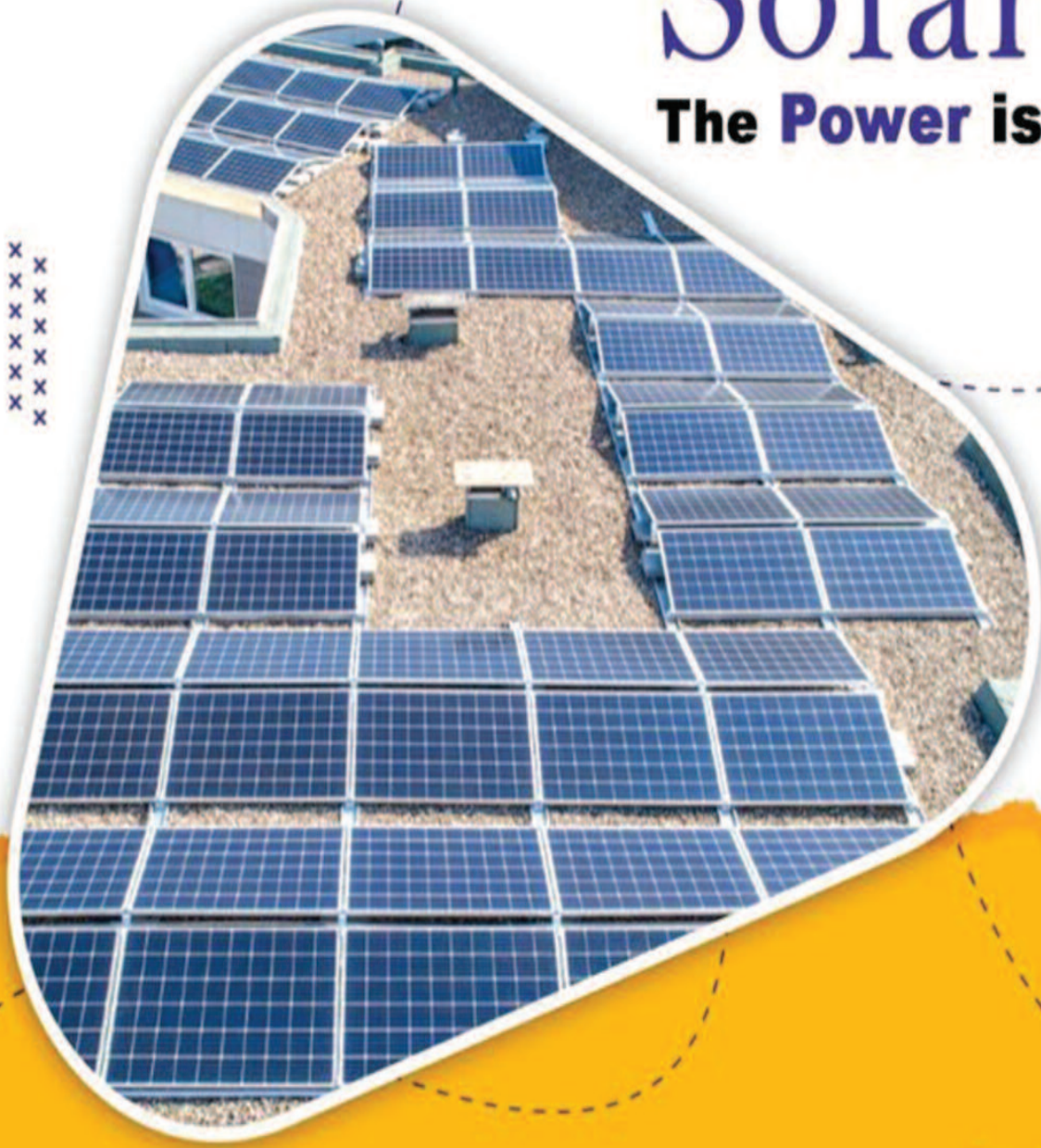

Harshita Electro & Telecom Pvt. Ltd.

SOLAR ON-GRID ROOFTOP SOLUTIONS | OFF GRID SOLAR SYSTEM
HYBRID SOLAR SYSTEM

Office : GF-135, Durga Tower, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad.
Phone : 9891116568, 9891116569, 9899562233

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

सनातन गर्व
महाकुम्भ पर्व
दिव्य-भव्य-डिजिटल
एकता का महाकुम्भ
महाकुम्भ प्रयागराज
2025
श्रद्धालुओं के साथ सरकार
डिजिटल महाकुम्भ
मुट्ठी में समाधान
वेबसाइट
https://kumbh.gov.in/
मोबाइल ऐप
Maha Kumbh Mela 2025
गूगल मैप्स इंटीग्रेशन
शौचालयों की तुरंत सफाई के लिए ऐप का इस्तेमाल
टॉयलेट की सफाई के लिए शौचालयों पर QR Code
किसी भी इमरजेंसी के लिए लाल रंग का QR Code
आवास, भोजन व पार्किंग के लिए ऐप पर जानकारी
मेला प्रशासन
आवास एवं आहार
कुम्भ सहायक चैटबॉट हेतु QR कोड स्कैन करें
कुम्भ सहायक
वाट्सऐप नं. 8887847135
पर 'नमस्ते' भेजें
13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025
महाकुम्भ 2025 प्रयागराज
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial
CMOUttarpradesh
CMOfficeUP
mahakumbh_25/
upmahakumbh
MahaKumbh_2025
https://kumbh.gov.in/